सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 255, नई दिल्ली । सोमवार, 25 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 सरकारी अस्पतालों में जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसरों की होगी नियुक्ति
06 चिरयुवा रहने की ललक में लुटते लोग
08 न हिंदुत्व न दल और न नेता ,जीती तो केवल लाड़ली बहना

दिल्ली सरकार से मेट्रो को 7200 करोड़ की दरकार

डीएमआरसी के एमडी ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को लिखा पत्र, राशि नहीं मिलने पर फेज-चार के तहत निर्माणाधीन कॉरिडोर में देरी होगी

संजय बाटला

नई दिल्ली। मेट्रो को दिल्ली सरकार से 7200 करोड़ रुपये की दरकार है। इसे लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक (एमडी) डॉ. विकास कुमार ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि यदि समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, तो फेज-चार के तहत निर्माणाधीन कॉरिडोर में देरी होगी। इससे लागत में भी बढ़ोतरी होगी।

दिल्ली मेट्रो के फेज-चार के तहत आरके आश्रम से जनकपुरी (पश्चिम), एरोसिटी-तुगलकाबाद और मुकुंदपुर से मौजपुर का निर्माण कार्य चल रहा है। तीनों कॉरिडोर को 2026 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। दोनों कॉरिडोर को इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इसके अलावा रिठाला से नाथूपुर तक एक और कॉरिडोर बनाने की संभावना है, लेकिन इसे अभी केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी नहीं मिली है।

24948 करोड़ में बन रहे तीन कॉरिडोर

डीएमआरसी के एमडी ने पत्र में कहा कि 62 किलोमीटर की लंबाई वाले फेज-चार के तीन निर्माणाधीन कॉरिडोर की लागत 24,948 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए नियमित रूप से धन की आवश्यकता है। इसके साथ 47 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले तीन अन्य कॉरिडोर के लिए भी धन की आवश्यकता है। बताया जा रहा है कि पत्र में एमडी ने कहा है कि समय पर धनराशि जारी करने की जरूरत है, ताकि परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।

पीडब्ल्यूडी को भी किया जाएगा भुगतान

दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से मेट्रो के फेज-चार के निर्माणाधीन कॉरिडोर के लिए डबल डेकर वायडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में डीएमआरसी ने दिल्ली सरकार से लोक निर्माण विभाग को 376 करोड़ रुपये जारी करने के लिए भी कहा है। यह डबल डेकर वायडक्ट के ऊपरी हिस्से पर मेट्रो चलेगी जबकि नीचे वाले हिस्से पर यातायात चलेगा। राजधानी में इस तरह के तीन डबल डेकर वायडक्ट का निर्माण होना है। इसमें एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर पर संगम विहार व अंबेडकर नगर स्टेशनों के बीच 2.4 किलोमीटर लंबा वायडक्ट, आजादपुर व रानी झांसी रोड चौराहे के बीच डबल डेकर वायडक्ट करीब 2.2 किलोमीटर लंबा होगा और भजनपुरा व यमुना विहार के बीच वाला वायडक्ट करीब 1.4 किलोमीटर लंबा

नोएडा मेट्रो में जॉब पाने का गोल्डन चांस, हर महीने मोटी सैलरी

मेट्रो में जॉब करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) में वैकेंसी निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू हो गई है। जिसमें अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं। नोएडा मेट्रो में नौकरी कैसे मिलेगी? योग्यता क्या होनी चाहिए? सबकुछ जानिए

मेट्रो में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जॉब पाने का गोल्डन चांस आ गया है। एनएमआरसी ने जनरल मैनेजर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट www.nmrcnoida.com पर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नोएडा मेट्रो की इस भर्ती में अभ्यर्थी आखिरी तारीख 19 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट के बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) की यह वैकेंसी जनरल मैनेजर (ऑपरेशंस) के लिए निकाली गई है। इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या इसके समकक्ष इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिक/मैकेनिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन/ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही काम का अनुभव भी मांगा गया है। योग्यता संबंधित अन्य डिटेल्स अभ्यर्थी विस्तार से भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। नोएडा मेट्रो की इस भर्ती में प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र आवेदन की आखिरी तारीख तक 56 वर्ष होनी चाहिए। इस पद पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सेलेक्शन प्रोसेस ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। इस पद पर सैलरी की बात करें तो जनरल मैनेजर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 1,20,000-2,80,000 रुपये वेतन दिया जाएगा।

नोएडा मेट्रो जनरल मैनेजर का यह पद डेप्यूटेशन के जरिए भरा जाएगा। जिसके लिए अभ्यर्थियों को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स नोएडा मेट्रो को भेजने होंगे। पता है- रजनरल मैनेजर/प्रोजेक्ट, फाइनेंस एंड एचआर, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ब्लॉक III, 3rd फ्लोर, गंगा शॉपिंग कॉम्पलैक्स, सेक्टर 29, नोएडा 201301, गौतम बुद्ध नगर, यूपी।ह इस भर्ती से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

वेटेज बेस्ड वोट प्रणाली क्या है? भारत देश में क्यों है जरूरी ?

संजय बाटला

सोचे और सही लगे तो सरकार से लागू करने की एकजुट होकर करे मांग।

1. एक परिवार में 12 लोग है

१. कोई भी डायरेक्ट इनकम टैक्स नही देता ।

2. एजुकेशन में भी उनमें से कोई ग्रेजुडेट नहीं है,

3. सरकार द्वारा घोषित सभी फ्री की योजनाओं का लाभ लेता है, अथवा

4. सब्सिडीका भरपूर फ़ायदा लेता है।

2. एक परिवार जिसमे 4 लोग हैं

१. सब के सब डायरेक्ट इनकम टैक्स देने वाले हैं

2. सब के सब हायर एजुकेटेड है

3. सरकार द्वारा घोषित किसी भी सब्सिडी या फ्री की योजना के लाभार्थी नहीं है।

वोटिंग प्रणाली में 12 सदस्य वाले के 12 वोट और 4 सदस्य वालों के 4 वोट यह समानता क्यों ?

सरकार को वोटिंग प्रणाली में **वेटेज बेस्ड वोट प्रणाली** को लागू कर टैक्स देने वाले/ सब्सिडी / फ्री योजना का फायदा नहीं लेने वालो के वोट की गिनती को मल्टीप्लायर घोषित करना चाहिए।

जैसे

1. आप पिछले 10 साल से लगातार 30% टैक्स दे रहे है तो आपका 1 वोट 10 वोट के बराबर और अगर आप 10% टैक्स देते हो आपका एक वोट 4 वोट के बराबर माना जाना चाहिए।

2. अगर आप किसी प्रकार की भी सब्सिडी या फ्री की योजना के लाभार्थी नही हैं तो आपका 1 वोट 5 के बराबर माना जाना चाहिए।

3. अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपका एक वोट 2 के बराबर और अगर आपके 6 बच्चे है तो 1 वोट को 1/2 आधे वोट के बराबर माना जाना चाहिए।

वोट प्रणाली में इस तरीके की व्यवस्था को लागू करने पर चिंतन करने का समय आ गया है। यदि समय रहते निर्णय नही लिया गया तो भारत देश हम 2 हमारे 12 वाले आने वाले पूरे देश पर राज करते नजर आएंगे।

यह मैसेज मेरे बेहद सकारात्मक चिंतक और मनन करने वाले राष्ट्र के सच्चे और अच्छे हितैषी ने प्रेषित किया है इसे मैने पड़ा और समझा तो मैं आप सभी से साझा करने से अपने को रोक न पाया। **बात देश की समृद्धि के प्रति विचार योग्य, दमदार और प्रशंसनीय है ।**

अनंतपुर में आरटीसी बस ने ऑटो को टक्कर मारी; सात की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

परिवहन विशेष न्यूज

अनंतपुर जिले के गार्ल्डिन मंडल में एपीआरसीटी बस और ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में सात लोगों की मौत और चार घायल हो गए। मृतक और घायल खेतिहर मजदूर हैं, जो काम करने के बाद ऑटो से वापस जा रहे थे।

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के गारल्डिने मंडल में थलागास्पाल्ले के पास एक आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम (एपीआरटीसी) और ऑटो की टक्कर हो गई। ऑटो में खेतिहर मजदूर सवार थे। दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अनंतपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, कुट्टलुरु मंडल के नेलुटला गांव के लगभग 12 खेतिहर मजदूर गार्ल्डिन में काम करने गए थे। वापसी में वह ऑटो से यात्रा कर रहे थे। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही एपीआरटीसी बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे के बाद दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बाद में, इलाज के दौरान तीन और लोगों की मौत हो गई।

पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया

जिले के एसपी जगदीश और डीएसपी वेंकटेश्वरुलु ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने एपीआरटीसी बस चालक को हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच की जा रही है।

मृतकों के परिवारों के लिए पांच लाख मुआवजे की घोषणा

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए पांच लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के लिए उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया।

मध्य प्रदेश को राज्य का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है. यह लगभग 1200 किलोमीटर लंबी सड़क राज्य के 11 जिलों से होकर गुजरेगी.

मध्य प्रदेश में बिछ रहा 1200 किलोमीटर लंबा रोड , 30 नेशनल हाईवे से होगा कनेक्ट

परिवहन विशेष न्यूज

मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है. इसका नाम नर्मदा एक्सप्रेसवे रखा गया है. यह एक्सप्रेसवे राज्य के 11 जिलों से गुजरते हुए करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा. इस एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 31,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

यह एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से 4 गुना बड़ा है. लगभग 30 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिलों की सड़कें नर्मदा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगी, जिससे इन 11 जिलों में विकास तेजी से होगा.

एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी

नर्मदा एक्सप्रेसवे का निर्माण अमरकंटक से अलीराजपुर जिले तक किया जा रहा है. यह एक्सप्रेसवे अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरोगन, बड़वानी और अलीराजपुर से होकर गुजरेगा.

एक्सप्रेसवे काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद

राज्य में जो हाईवे नर्मदा एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं, वे फिलहाल टू-लेन हैं, लेकिन भविष्य में इन्हें चौड़ा किया जाएगा. तब ये टू-लेन हाईवे फोर-लेन में बदल जाएंगे. इस एक्सप्रेसवे काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है.

मध्य प्रदेश से दो राज्यों को भी जोड़ेगा

नर्मदा एक्सप्रेसवे गुजरात और छत्तीसगढ़ को जोड़ेगा. यह अलीराजपुर को अहमदाबाद से और अनूपपुर जिले को छत्तीसगढ़ से जोड़ेगा.

नर्मदा एक्सप्रेसवे से टूरिज्म को बढ़ावा

नर्मदा एक्सप्रेसवे से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. यह न केवल मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात और छत्तीसगढ़ को भी लाभान्वित करेगा. नर्मदा एक्सप्रेसवे से इन 3 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी. ओंकारेश्वर, अमरकंटक और भेड़ाघाट-लमेताघाट जैसे पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा आरामदायक होगी. नर्मदा एक्सप्रेसवे से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और तीनों राज्यों में निवेश के अवसर भी आएंगे।

दिल्ली-पिलानी नेशनल हाईवे 709-ई पर जाम बना मुख्य समस्या

जूई। कस्बे में दिल्ली-पिलानी नेशनल हाईवे 709-ई पर हर रोज जाम लग रहा है। जाम लगा रहने से राहगीरों के अलावा आमजन भी परेशान हैं। पिछले 10 साल से जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

ऐसा नहीं है कि जाम से निजात के लिए प्रयास नहीं किए गए। जूई थाना के कर्मचारी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यातायात इतना ज्यादा हो गया है कि जाम की स्थिति बन ही जाती है। ऊपर से सड़क किनारे खड़े वाहन और रेहड़ी वाले भी समस्या को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ग्रामीणों की मांग है कि बाईपास बनने से पहले जूई में सड़क मार्ग पर बीच में डिवाइडर बन जाए तो बात बने।

सालों पुरानी मांग पर न जाने कब होगा समाधान

जूई में जाम लगना आम बात हो गई है। निजी वाहनों के चालक वाहनों को सड़क किनारे खड़े कर बजारिया करने वाले व्यवस्था को चौपट करने का काम करते हैं। ग्रामीण भीमसिंह, मांगेराम, सतीश कुमार, बिजेंद्र, बिल्लू लाम्बा बताते हैं कि दो दशक पहले होली के दिनों में इस सड़क पर खुलियां खेलते थे। यातायात बहुत कम था, लेकिन अब सड़क पार करने को 5 मिनट इंतजार करना पड़ता है। अब तो सड़क मार्ग पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर डिवाइडर बन जाए तो कुछ राहत मिलेगी।

जल्द बने बाईपास : बृजेश

जूई निवासी बृजेश ने बताया कि यातायात बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जूई में एक बाईपास बनाना बहुत जरूरी है ताकि राहगीरों, दुकानदारों व आमजन को राहत मिल सकती है।

सांसद कर रहे हैं प्रयास : राजेश

जूई बिचली निवासी राजेश लांबा बताते हैं कि गांव की फिलहाल सबसे बड़ी समस्या जाम बन गई है। इसके लिए भिवानी-महेंद्रगढ़ सांसद धर्मबीर सिंह प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के प्रयास रंग लाएंगे। गांव को समस्या से जल्द निजात मिलेगी।

अब उम्मीद जगी है : महेंद्र

जूई बिचली निवासी महेंद्र सिंह कहते हैं कि वर्तमान में उम्मीद जगी है कि सालों पुरानी ये मांग जल्द पूरी होगी। इसके लिए सांसद धर्मबीर सिंह के पत्र पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। बाईपास बनते ही गांव की सालो पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। लोगों को राहत मिलेगी।

पिछले साल के पुराने स्वेटर को क्यों फेंकना, इन तरीकों से करें दोबारा इस्तेमाल

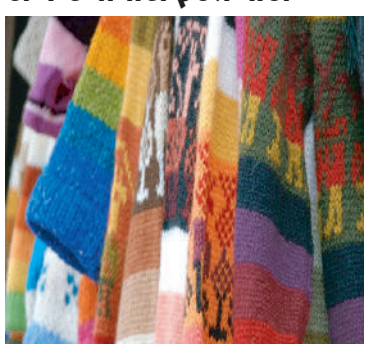

अगर आप चाहें तो अपने पुराने स्वेटर को बतौर तकिए के कवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बिस्तर पर लेटते समय भी गरमाहट का अहसास होगा। इसके लिए आप स्वेटर के मुख्य भाग को काट लें, इसे सिल लें और अंदर एक तकिया रख दें।

ठंड का मौसम आ चुका है और हम सभी ने बेड व अलमारी में स्टोर करके रखे हुए गर्म कपड़ों को दोबारा निकालना शुरू कर दिया है। इस मौसम में कंबल से लेकर स्वेटर तक कई तरह के गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होती है। लेकिन जब आपने पिछले साल के गर्म कपड़ों को निकाला होगा तो देखा होगा कि बहुत सारे कपड़े या तो छोटे हो चुके होते हैं या फिर आपका उन्हें इस साल पहनने का मन नहीं करता। ऐसे में समझ नहीं आता कि उन पुराने स्वेटर का क्या किया जाए। अगर आप चाहें तो इन पुराने स्वेटर की मदद से भी काफी कुछ बना सकते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको इस लेख में बता रहे हैं-

बनाएं तकिए का कवर

अगर आप चाहें तो अपने पुराने स्वेटर को बतौर तकिए के कवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बिस्तर पर लेटते समय भी गरमाहट का अहसास होगा। इसके लिए आप स्वेटर के मुख्य भाग को काट लें, इसे सिल लें और अंदर एक तकिया रख दें। अब आप इस तकिए को अपने बेडरूम में इस्तेमाल कर सकती हैं।

तैयार करें स्वेटर कंबल

आपको शायद पता ना हो, लेकिन पुराने स्वेटर की मदद से स्वेटर कंबल भी तैयार किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए आपको कई सारे स्वेटर की जरूरत होगी। बस आप इन्हें एक साथ सिल लें और फिर पैचवर्क रजाई की तरह तैयार करें। यह स्वेटर कंबल देखने में बेहद ही आकर्षक लगता है।

घर पर ही बनाएं दस्ताने

पुराने स्वेटर की मदद से दस्ताने बनाना भी एक अच्छा आइडिया है। इसके लिए आप स्वेटर की आस्तीन आदि का इस्तेमाल कर सकती हैं। बस आप इसे दस्ताने के आकार में काट लें और फिर उन्हें एक साथ सिल लें। बस इस तरह घर पर बना हैंड वार्मर पहनने के लिए तैयार है।

बनाएं वास कवर

अगर आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए वास का इस्तेमाल करती हैं तो अब इसके लिए वास कवर बनाकर तैयार करें। इसके लिए आप स्वेटर के छोटे टुकड़े काटें और उन्हें जार या फूलदान के चारों ओर लपेटने के लिए उपयोग करें। विंटर के अनुसार यह घर को एक न्यू लुक देने का बेहतरीन तरीका है।

बच्चे के जन्म के बाद खाएं ये मसाले, जल्द होगी रिकवरी

हल्दी के अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। यह आपके आंतरिक घावों को ठीक करने और डिलीवरी के बाद की सूजन को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ, यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके इंफेक्शन से बचाता है।

बच्चे के जन्म के बाद एक मां को अपने आहार पर बहुत अधिक ध्यान देना होता है। जब नई मां अच्छा आहार लेती है तो इससे ना केवल उसे रिकवरी में मदद मिलती है, बल्कि ब्रेस्टमिल्क भी बढ़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ मसालों व हर्ब्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ये मसाले कई तरह के एंटी-ऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जिससे आपके शरीर को ताकत मिलती है। हल्दी, मेथी, अजवायन और जीरा जैसे मसाले अपनी हीलिंग प्रोपर्टीज के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ, इन मसालों से आपको अन्य भी बहुत अधिक लाभ मिलते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ मसालों व हर्ब्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें एक नई मां को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए-

हल्दी

हल्दी के अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। यह आपके आंतरिक घावों को ठीक करने और डिलीवरी के बाद की सूजन को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ, यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके इंफेक्शन से बचाता है। आप हल्दी का दूध ले सकते हैं या फिर सूप और दाल आदि में इसे शामिल कर सकते हैं।

मेथी

मेथी अपने फाइटोएस्ट्रोजेन के कारण ब्रेस्टमिल्क के उत्पादन को बढ़ाता है। यह ना केवल पाचन में सहायता करता है, बल्कि सूजन को भी कम करता है। साथ ही साथ, इससे जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करने में मदद मिलती है। मेथी के लड्डू के रूप में इसका सेवन किया जा सकता है, करी में मिलाया जा सकता है, या मेथी चाय के लिए पानी में उबाला जा सकता है।

अजवाइन

अजवाइन की मदद से प्रसव के बाद होने वाली आम समस्याओं गैस, सूजन और अपच से राहत मिलती है। इसमें एंटी-माइक्रोबायल प्रोपर्टीज भी पाई जाती हैं, जो इंफेक्शन को दूर करने में मददगार है। आप अजवाइन को पानी में उबालकर इसका इस्तेमाल करें या फिर अजवाइन के पराठे की तरह फ्लैटब्रेड में मिला लें।

सौंफ़

सौंफ के सेवन से ब्रेस्टमिल्क प्रोडक्शन बेहतर होता है। साथ ही साथ, यह पाचन में सुधार करता है और कब्ज से बचाता है। आप कच्ची सौंफ को यूं ही चबा सकते हैं या फिर सौंफ का पानी पीएं। आप इसे चाय और मिठाई का हिस्सा भी बना सकते हैं।

चेहरे पर नींबू का ऐसे करें इस्तेमाल, नहीं होगा कोई नुकसान

अगर आप चेहरे पर नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हमेशा इसे डायलूट करके ही लगाना चाहिए। सीधे नींबू चेहरे पर लगाने से आपको इरिटेशन व जलन आदि हो सकती है। आप इसमें पानी के अलावा शहद, दही या कैरियर ऑयल आदि को मिक्स कर सकते हैं।

स्किन की केयर करने के लिए हम सभी कई तरह के होम इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना बेहद आम है। इन्हीं में से एक है नींबू। विटामिन सी रिच होने की वजह नींबू को एक स्किन ब्राइटनिंग एजेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। यह ना केवल आपकी स्किन को अधिक चमकदार बनाता है, बल्कि इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण भी आपको काफी फायदा पहुंचाता है। नींबू के इस्तेमाल से डार्क स्पॉट्स, डेड स्किन सेल्स व अतिरिक्त तेल को कम करने में मदद मिलती है।

इस बात में कोई दोराय नहीं है कि नींबू का इस्तेमाल करना स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन यह काफी एसिडिक होता है, जिसकी वजह से आपको जलन से लेकर सूखापन और सन सेंसेटिविटी आदि की शिकायत हो सकती है। इसलिए, नींबू का इस्तेमाल बेहद सोच-समझकर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि स्किन केयर के लिए नींबू का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए-

करें डायलूट

अगर आप चेहरे पर नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हमेशा इसे डायलूट करके ही लगाना चाहिए। सीधे नींबू चेहरे पर लगाने से आपको इरिटेशन व जलन आदि हो सकती है। आप इसमें पानी के अलावा शहद, दही या कैरियर ऑयल आदि को मिक्स कर सकते हैं।

करें स्पॉट टेस्टिंग

जब आप नींबू को स्किन पर लगा रही हैं तो ऐसे में आप स्पॉट टेस्टिंग जरूर करें। आप इसे चेहरे पर लगाने से पहले अपने कान के पीछे या अपनी कलाई पर लगाएं और करीबन 24 घंटे तक इंतजार करें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि नींबू से आपकी स्किन पर कोई विपरीत रिएक्शन नहीं हो रहा है।

दिन में इस्तेमाल करने से बचें

जब आप स्किन पर नींबू लगा रही हैं तो ऐसे में आपको इसे सही समय पर लगाना चाहिए। कई बार लोग दिन में नींबू को स्किन पर लगाते हैं। लेकिन इससे सन सेंसेटिविटी की शिकायत हो सकती है। इसलिए, फोटोसेंसिटिविटी से बचने के लिए आप नींबू या नींबू बेस्ड उपचारों का इस्तेमाल दिन के बजाय रात में करें।

सर्दियों में ठूस-ठूस कर खाने से फूलने लगा पेट, तो इन 5 टिप्स से मिलेगी राहत

सर्दियों के दौरान उल्टा-पुल्टा खाने से पेट संबंधित समस्याएं बढ़ने लगती है। कई बार हेल्दी खाने के बाद भी पेट फूलने की समस्या देखने को मिलती है। इसे ब्लोटिंग भी कहते हैं, पेट में गैस भरे रहने से और पेट फूलने लगता है। आइए आपको बताते हैं इससे छुटकारा जल्द ही पाने के लिए किचन में रखी इन चीजों से किया जा सकता है।

सर्दियों के मौसम हर एक खाने की चीज स्वादिष्ट लगती है। टेस्टी व्यंजन स्वाद हम सभी काफी चखते हैं। कई बार तो इतना खा लेते हैं कि जिसे पचा पाना बना काफी मुश्किल होता है। कई बार पेट की परेशानियां उल्टा-पुल्टा खाने से भी होता है, जिससे पेट फूलने की समस्या होने लगती है। अक्सर हेल्दी डाइट लेने और एक्सरसाइज करने के बाद भी पेट फूलने की समस्या होने लगती है। ब्लोटिंग से राहत पाने के लिए आप किचन में रखीं इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं।

अदरक

अगर सर्दियों में आपका भी कुछ भी खाने से पेट फूलने लगता है, तो आप इसे राहत पाने के लिए यह उपाय जरुर करें। हर घर में अदरक का इस्तेमल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही यह पेट के लिए काफी लाभकारी है। अदरक की हर्बल चाय पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त रहता है और इससे ब्लोटिंग को दूर करता है।

सौंफ

सौंफ का सेवन नेचुरल माउथ फ्रेशनर के तौर पर किया जाता है। जिससे मुंह की दुर्गंध दूर होती है। लेकिन इसका इस्तेमाल ब्लोटिंग की समस्या को दूर करता है।

पुदीना

पुदीना में आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं, इसकी तासीर ठंडी होती है। यह पेट को राहत पुहंचाने का काम करता है। आप चाहे तो एक कप पुदीने की चाय पिएंगे तो पेट के मसल्स को आराम मिलेगा और ब्लोटिंग से भी निजात मिलेगा।

जीरा

पेट फूलने की समस्या से बचने के लिए आप जीरा का प्रयोग कर सकते हैं। एक चम्मच साबुत जीरा एक कप पानी में मिलाएं और इसे उबाल लें। जब यह गुनगुना हो जाए तो इसे धीरे-धीरे जरुर पिएं।

नींबू

वैसे नींबू पाचन तंत्र के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर आपको पेट फूलने की तकलीफ रहती है तो आप एक ग्लास गुनगुना पानी लें और उसमें एक नींबू को निचोड़ लें और पी जाएं। इससे न सिर्फ बॉडी डिटॉक्स होगी और पेट फूलने की समस्या दूर हो जाएगी।

आखिर अडानी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं 'अमेरिकी'? इसे ऐसे समझिए

ऐसे में यह स्वाभाविक सवाल है कि जब भारत में रिश्वत देने के आरोप लगाए गए हैं तो फिर केस यूएस यानी अमेरिका में क्यों? इसका जवाब यही है कि अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजारों से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है।

-कमलेश पांडे

जिस तरह से दुनिया के थानेदार अमेरिका में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अदाणी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, उसके दृष्टिगत यह सवाल मौजूं है कि जब रिश्वत का आरोप भारत में लगाया गया है तो फिर अमेरिका में जांच कैसे शुरू हो गई? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और उसके लोग, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के चहेते उद्योगपति अडानी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं? क्या किसी भारतीय उद्योगपति या राजनीतिक दल के शह पर ऐसा किया जा रहा है या फिर कोई अन्य कूटनीतिक वजह है?

क्योंकि यह महज इत्तेफाक नहीं समझा जा सकता है कि पिछले साल 2023 में अमेरिकी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से शुरू हुए विवाद के बाद अब वर्ष 2024 में अदाणी समूह पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का उछला ताजा मामला एक अदद मामला भर है? वजह यह कि इससे अडानी समूह के शेयरों के भाव गिरते हैं और कम्पनी को काफी क्षति उठानी पड़ती है! इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि आखिर में यह मामला क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है? और अंत में, इसका समुचित हल क्या है? आइए इस पूरी बात को क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।

बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने अदाणी पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (2200 करोड़ रुपए से ज्यादा) की रिश्वत देने का आरोप लगाया है, जो एक गम्भीर बात है। क्योंकि यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने आरोप में कहा है कि अदाणी ने अपनी कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकायों को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी है।

मसलन, अदाणी पर आरोप है कि उन्होंने 2021 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद राज्य सरकार 7,000 मेगावाट बिजली खरीदने पर सहमत हुई थी। आंध्र के अधिकारियों को 25 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से कथित रिश्वत दी गई। इसके अलावा, अमेरिकी सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। खास बात यह है कि उन्होंने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इंवेस्टर्स से छिपाया है, जिनसे अदाणी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे।

लिहाजा, अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स का दावा है कि कंपनी के दूसरे सीनियर अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को पैसा देने पर सहमति जताई थी। बता दें कि अडानी समूह ने साल 2021 में एक बॉन्ड ऑफर कर अमेरिका के अलावा दूसरे इंटरनैशनल इंवेस्टर्स और अमेरिका के बैंकों से फंड जुटाया है। अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) ने बयान में कहा है कि कथित साजिश के तहत अदाणी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 17.5 करोड़ डॉलर से अधिक जुटाए और एज्यूर पावर का शेयर न्यूयॉर्क शेयर बाजार में लिस्टेड किया। साथ ही, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने अदाणी, सागर अदाणी, सिरिल कैबनेस और अदाणी ग्रीन और एज्यूर पावर से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए हैं।

वहीं, अदाणी ग्रुप ने रिश्वतखोरी के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया है। उसने कहा है कि ग्रुप सभी कानूनों का पालन करता रहा है। वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। ग्रुप के प्रवक्ता ने अमेरिकी न्याय विभाग के बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया जिसका अडानी पर यह केवल आरोप है और जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाएगा। लिहाजा, बयान में कहा गया कि हम आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन है। अदाणी ग्रुप ने अदाणी ग्रीन एनर्जी लि. के 60 करोड़ डॉलर के बॉण्ड को रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में ठेका मिला है।

ऐसे में यह स्वाभाविक सवाल है कि जब भारत में रिश्वत देने के आरोप लगाए गए हैं तो फिर केस यूएस यानी अमेरिका में क्यों? इसका जवाब यही है कि अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजारों से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। चूंकि, प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है, इसलिए अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ।

चूंकि अमेरिका भारत का मित्र देश भी है, इसलिए ये आरोप अहम हैं। हालांकि, जिस तरह से अमेरिकी चुनावों में परास्त राष्ट्रपति जो बाइडेन के मातहत प्रशासन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को भड़काने और भारत के उद्योगपति को भ्रष्टाचार के मामले में उलझाने की पहल जाते-जाते की है, इसके अंतर्राष्ट्रीय सियासी मायने को भी समझने की जरूरत है। शायद वह भावी ट्रंप प्रशासन के लिए मुश्किलें पैदा करना चाहता हो।

सवाल यह है कि आखिर यह हंगामा किन-किन प्रोजेक्ट्स को लेकर मचा है? तो जवाब यही होगा कि अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार, एनर्जी कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदाणी है। अदाणी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदाणी है, जो उनके भतीजे हैं। इसके अलावा, एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता, एज्योर पावर में सलाहकार रूपेश अग्रवाल अमेरिकी इश्यूअर हैं।

हुआ यह है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी और अमेरिकी इश्यूअर ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था।

हालांकि, एसईसीआई को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाए। लिहाजा खरीदारों के बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता था और दोनों कंपनियों के सामने बड़े नुकसान का जोखिम था। इसलिए अदाणी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई। तो फिर यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर में रिश्वत का हिस्सा किनको किनको मिला? उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा किनको मिला? इसके जवाब भी अमेरिकी प्रशासन के आरोपों से मिलते हैं।

अमेरिकी प्रशासन के आरोपों के मुताबिक, इन लोगों ने तय किया कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो राज्य बिजली वितरण कंपनियों को एसईसीआई के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। शायद इसलिए उन्होंने भारतीय अफसरों को करीब 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया। फलाफल यह निकला कि इसके बाद कुछ राज्य बिजली कंपनियां सहमत हुईं और दोनों कंपनियों से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए एसईसीआई के साथ समझौता किया।

इससे साफ है कि भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी इश्यूअर ने मिलकर रिश्वत का भुगतान किया। इतना ही नहीं, अपनी संलिप्तता छिपाने के लिए कोड नामों का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय (न्यू यॉर्क) के अनुसार, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनमें गौतम एस. अदाणी, सागर एस. अदाणी, विनीत एस. जैन, रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल के नाम प्रमुख हैं।

हालांकि, अमेरिकी कानूनों के तहत ऐसे मामलों में आमतौर पर डेफर्ड प्रॉसिक्यूशन एग्रीमेंट्स या नॉन प्रॉसिक्यूशन एग्रीमेंट्स के जरिए सेटलमेंट की इजाजत है। जिसके मुताल्लिक कुछ गलतियां स्वीकार करने, नियमों का अनुपालन बेहतर करने के वादे और जुर्माना चुकाने के साथ ही यह मामला सुलझाया जा सकता है। इससे पहले भी सीमेंस ने 80 करोड़ डॉलर और एरिक्सन ने 1 बिलियन डॉलर का जुर्माना चुकाया था। लिहाजा, अदाणी ग्रुप भी चाहे तो ऐसा कुछ कर सकता है।

कहना न होगा कि हिंडनबर्ग मामले के चलते अमेरिका में अदाणी ग्रुप की कंपनियों का बाजार मूल्य जितना घटा था, उससे दोगुनी गिरावट अमेरिकी अदालत में ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी पर लगे आरोपों के चलते आई है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला ग्रुप की साख के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, लेकिन अमेरिका में इस मामले के निपटारे के रास्ते भी की कंपनियों के शेयर इस गिरावट से जल्द उबर सकते हैं, हालांकि निवेशकों को फिलहाल सेटलमेंट की गुंजाइश चुनिंदा है।

सवाल है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की संभावित नीतियों, चीन में राहत पैकेज और रूस-यूक्रेन संकट गहराने और इजरायल-फिलिस्तीन विवादों के बढ़ते चले जाने के चलते भारतीय शेयर बाजार में पहले से ही कमजोरी दिख रही थी। फिर, अडाणी मामले ने इसे और हिला दिया। अलबत्ता, ताजा मामले का इस ग्रुप पर जैसा भी असर पड़े, लेकिन इतना तय है कि देश की इकॉनमी पर आंच नहीं आने जा रही। भारत में लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था का दमखम, कंपनियों के मुनाफे में अच्छी बढ़त और रेगुलेटरी साख ही शेयर बाजार के लिए अहम है। ऐसे में भारत पर दांव लगाने वाले विदेशी निवेशक इन चीजों को नजरंदाज नहीं करने जा रहे।

इस पूरे मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि जब भी भारत में संसद सत्र शुरू होने वाला होता है तो भारत के प्रतिपक्ष को अमेरिका एक नया मुद्दा थमा देता है। अब जबकि सोमवार 25 नवम्बर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो यह नया मामला सामने आ गया। लिहाजा, उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों पर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग की। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष के नाते वह और पूरा विपक्ष अदाणी से जुड़े मामले को उठाएगा।

बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अदाणी पर लगे आरोपों पर कहा कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह दावा भी किया कि गौतम अदाणी की गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और वह एक हैं और इसीलिए दोनों सेफ हैं। यह राजनीतिक, वित्तीय और अफसरशाही से जुड़े लोगों का पूरा नेटवर्क है। एक तरफ ये नेटवर्क देश के राजनीतिक तंत्र को कब्जे में करता है, दूसरी तरफ मुनाफे का काम करता है। इसलिए सेबी चीफ माधवी पुरी बुच को पद से तुरंत हटाकर जांच हो।

वहीं, कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद व प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी 2002 से ही नरेन्द्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं हुए है। राहुल गांधी ने आज जिस तरह का व्यवहार दिखाया है, यह कोई नई बात नहीं है। कंपनी के खिलाफ अमेरिका के आरोपों में जिन चार राज्यों का जिक्र है, उनमें से किसी में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं था। गांधी परिवार और कांग्रेस ये सहन नहीं कर पा रहा है कि भारत लगातार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि ये भारत की मार्केट पर आक्रमण कर रहे हैं। आज सुबह चार बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर भारत के शेयर मार्केट को गिराने में लगा हुआ है। इससे करीब 2.5 करोड़ छोटे निवेशकों को नुकसान हुआ है।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों में अदाणी ग्रुप के निवेश का हवाला देते हुए पात्रा ने कहा कि समूह ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के दौरान 25 हजार करोड़ रुपये और 65 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया था। बीजेपी ने राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए तंज कसते हुए कहा कि वह भले ही पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनकी विश्वसनीयता इतनी ही है कि हाल ही में विदेश में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सांसद संबित पात्रा ने कहा कि यह कंपनी का काम है कि वह स्पष्टीकरण दे। कानून अपना काम करेगा। आरोपों में जिन राज्यों का जिक्र है, उनमें उस समय विपक्षी दलों का ही शासन था।

आसान नहीं है दिल्ली की राह, पंजाब में जीत का कितना होगा फायदा? पढ़ें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जानकारों का मानना है कि आप के लिए इस बार राह आसान नहीं होगी। भाजपा केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आप भी इसे भांप कर अतिरिक्त मेहनत की तैयारी में जुट गई है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा उपचुनाव में चार में से तीन सीटें मिल गई हैं, आप इससे उत्साहित है और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल भी बता रही है। मगर राजनीति के जानकार आप के लिए इस बार राह आसान नहीं मान रहे हैं।

उनकी मानें तो इस बार जिस तरह आप नेता जेल जाकर बाहर आए हैं, उससे माहौल बिगड़ा है और खासकर केजरीवाल के जेल जाने से उनकी छवि को नुकसान भी हुआ है। भाजपा इसे ही मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आप भी इसे भांप कर अतिरिक्त मेहनत की तैयारी में जुट गई है।

और भी विधायकों के टिकट कटने के संकेत

इसी रणनीति के तहत आप अब तक अपने तीन विधायकों के टिकट काट चुकी है, अभी और भी विधायकों के टिकट कटने के आप से संकेत दिए हैं। आप नेतृत्व इस बार उन्हीं लोगों को मैदान में उतार रहा है, जिन पर उन्हें जीतने का पूरा भरोसा है और जो उनके सर्वे में फिट बैठ रहा है। इसी के चलते अब तक आप भाजपा के तीन-तीन नेताओं को पार्टी में शामिल करा चुकी है और सबसे पहले उन्हें टिकट देने की घोषणा भी कर चुकी है।

भ्रष्टाचार के आरोपों को आधार बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी

आप ने जो 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं उनमें से ज्यादातर उनके पास नहीं हैं। अब अगर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा इस बार केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को आधार बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी में है। उस समय उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल भी जेल में रह कर आए हैं। आप भी यह बात कह रही है कि भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

गहलोत के पार्टी छोड़ने से बढ़ी मुश्किलें

मुख्यमंत्री आवास में अनियमितताओं का मुद्दा भी भाजपा उठा रही है। भाजपा भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर चुनाव में उतरनी की तैयारी में है। इसी दौरान केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत आप से इस्तीफा देकर एकाएक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में केजरीवाल के लिए इस चुनाव में चुनौती बढ़ चुकी है।

ईमानदारी को हथियार बना रहे आप नेता

उधर आप का कहना है कि जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार हैं। केजरीवाल भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर यह घोषणा कर चुके हैं फिर से अगर जनता उन्हें चुनेगी तभी वह मुख्यमंत्री बनेंगे, केजरीवाल भी सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर चुके हैं कि जनता उन्हें उन्हें ईमानदार मानती है तो उन्हें वोट दे। आप का कहना है कि केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी इतनी बड़ी बात कह पा रहे हैं।

गोवा की काजू और तमिलनाडु का कंगन ने खरीदारों को लुभाया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 43वें विश्व व्यापार मेले में *केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर)* द्वारा समर्थित सरस आजीविका मेला का आयोजन भारत मंडपम के हॉल नंबर–9 और 10 में किया गया है। सरस आजीविका मेला में 10 से *20 प्रतिशत तक की भारी छूट* के कारण जमकर खरीदारी हुई। सरस पवेलियन में 20 प्रतिशत तक की बंपर डिस्कॉउंट के कारण सभी स्टॉलों पर बंपर खरीदारी हुई। गोवा की नव दुर्गा स्वयं सहायता समूह की निशा विष्णुदास गावकर बताती हैं कि वह अपने स्टॉल नंबर 127 पर विभिन्न प्रकार के काजू, बनाना चिप्स, कोकम, गरम मशाले आदि लेकर आई हुई हैं, जिसकी भरपूर बिक्री हो रही है। निशा ने बताया कि उनके स्टॉल पर सॉल्टेड काजू, रोस्टेड काजू, छिलके वाले काजू की जममकर खरीदारी हो रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग पांच सौ किलो काजू की बिक्री हो चुकी है। उनके यहां दो सौ से 360 रुपये तक के सामान हैं। उनका कहना है कि दिल्ली वालों को छिलके वाले काजू ज्यादा पसंद हैं इसकी बिक्री भी अधिक हुई है।

वहीं, केरला के श्री स्वयं सहायता समूह के प्रमिला और भुवनेश्वरी बताती हैं कि उनके स्टॉल नंबर तीन पर केरला साड़ी, ड्रेस मेटेरियल, लुंगी, धोती, टूपिस साड़ी, लहंगा समेत तामाम आयटम हैं। उनके यहां पांच सौ से लेकर पचपन सौ रुपये तक के सामान हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु का कंगन भी महिलाओं को सरस में काफी आकर्षित कर रहा है। गोल्डेन कंगन महिलाओं को ऐसे लुभा रहा कि बिना खरीदे रहा नहीं जा रहा।

ज्ञात हो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा समर्थित सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन भारत मंडपम में 43वें विश्व व्यापार मेले में किया गया है। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव में 31 राज्यों की 300 से अधिक महिला शिल्प कलाकार, 150 से अधिक स्टॉलों पर अपनी-अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शनी का प्रदर्शन व बिक्री कर रही हैं। सरस आजीविका मेला भारत मंडपम के हॉल नंबर– 9 और 10 में लगाया गया है। सरस आजीविका मेला के दौरान देश भर के 31 राज्यों के हजारों उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री हो रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के एडहॉक पदों को समाप्त किया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस (शिक्षक संगठन) के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन प्रोफेसर एम.जगदीश कुमार को पत्र लिखकर मांग की है कि विश्वविद्यालय के विभागों व संबद्ध कॉलेजों, एसओएल, नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड में पढ़ा रहे 4 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों को भी सहायक प्रोफेसर स्थायी नियुक्तियों के समय वरीयता दिए जाने की मांग की है। बता दें कि पिछले दो साल से दिल्ली विश्वविद्यालय ने एडहॉक पदों को समाप्त कर दिया है, उसके स्थान पर अब अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से डीयू के कॉलेजों में स्थायी नियुक्ति के समय एडहॉक टीचर्स के शिक्षण अनुभव को जोड़ा जा रहा है उसी तरह से अतिथि शिक्षकों को भी नियुक्ति व प्रमोशन में वरीयता दिए जाने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि स्थायी नियुक्तियों के समय अतिथि शिक्षकों के शिक्षण अनुभव को कोई भी शिक्षण संस्थान/कॉलेज नहीं मानते है जबकि उनकी योग्यता किसी भी स्तर पर कम नहीं है। उनका यह भी कहना है कि यूजीसी ने 2019 के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों में स्थायी नियुक्ति की भांति सलेक्शन कमेटी बिठाने संबंधी अधिसूचना जारी की हुई है और उसी के तहत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

फोरम के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने यूजीसी चेयरमैन को लिखे पत्र में उन्हें बताया है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में नए नियमों के अनुसार एडहॉक टीचर्स से ज्यादा पेचीदा हैं। नए नियमों के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के समय दो विषय विशेषज्ञ (सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट) ऑब्जर्वर, वाइस चांसलर नॉमिनी, विभाग प्रभारी और प्रिंसिपल सलेक्शन कमेटी में बैठते हैं जबकि एडहॉक टीचर्स की नियुक्ति में कॉलेज प्रिंसिपल, विभाग प्रभारी, वरिष्ठ शिक्षक व ऑब्जर्वर ही नियुक्ति करते हैं। उन्होंने बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दो तरह की गेस्ट फैकल्टी है एक जो प्रिंसिपल के द्वारा नियुक्ति होती है जिसे अधिकतम 25 हजार रुपये दिए जा सकते हैं और दूसरे वह जिसमें यूजीसी द्वारा जनवरी 2019 के बाद आई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी गाइडलाइंस जिसके अंतर्गत 50 हजार रुपये तक दिए जा सकते हैं।

डॉ. सुमन ने बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में दोनों तरह के अतिथि शिक्षक है जबकि स्कूल ऑफ़ लर्निंग (एसओएल) व नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को एक सेमेस्टर में 25 दिन दिए जाते हैं जिसमें प्रति दिन 2 क्लासेज लेनी पड़ती है, वहीं दूसरे सेमेस्टर में भी यहीं नियम है। लेकिन एसओएल में एक सेमेस्टर में 20 क्लासेज दी जाती है। इन दोनों स्थानों पर यूजीसी के नियमानुसार 1500 रुपये प्रति लेक्चर के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। उन्होंने बताया है कि इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में 4000 अतिथि शिक्षक है जो एसओएल, नॉन कॉलेजिएट वीमेंस बोर्ड व रेगुलर कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। डॉ. सुमन के अनुसार नॉन कॉलेजिएट में लगभग 1300 शिक्षक (26 सेंटर) एसओएल में लगभग 1500 शिक्षक व रेगुलर कॉलेजों में लगभग-1300 अतिथि शिक्षक है। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में इग्नू की क्लासेज भी लगती है जिसमें अतिथि शिक्षकों की भांति एकेडेमिक काउंसलर रखे जाते हैं।

डॉ. सुमन ने बताया है कि इन अतिथि शिक्षकों की योग्यता व एडहॉक शिक्षकों की योग्यता में कोई अंतर नहीं है बल्कि यूजीसी द्वारा 2019 के बाद नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया है वह ज्यादा कठिन है। एडहॉक शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए भी एम.ए., एम.कॉम.एमएससी नेट/जेआरएफ होना अनिवार्य है तो वहीं अतिथि शिक्षकों के लिए। एम. फिल/पीएचडी अतिरिक्त योग्यता है। दोनों को बराबर कार्य करना पड़ता है एडहॉक शिक्षकों की भांति उन्हें भी ,एग्जामिनेशन ड्यूटी, परीक्षा मूल्यांकन ,असाइनमेंट चेक करना, उनके अंक चढ़ाना आदि कार्य करने पड़ते हैं। एसओएल व नॉन कॉलेजिएट की कक्षाएं शनिवार और रविवार के अलावा जब रेगुलर कॉलेजों की छुट्टियां होती है तब 26 सेंटर पर कक्षाएं लगती है। यहाँ पर अधिकार विभिन्न विभागों से पीएचडी कर रहे शोधार्थियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

उन्होंने यह भी बताया है और चिंता जाहिर की है कि इन अतिथि शिक्षकों को डूटा व विद्वत परिषद व कार्यकारी परिषद (एसी/ईसी) में वोट डालने का अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि उन अतिथि शिक्षकों को तो कम से कम वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए जो यूजीसी गाइडलाइंस --2019 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। साथ ही उनका शिक्षण अनुभव भी नियुक्ति व पदोन्नति में जोड़ा जाए। डॉ. सुमन ने यूजीसी से यह भी मांग की है कि वह नियुक्ति और पदोन्नति के समय अतिथि शिक्षकों को शिक्षण अनुभव (टीचिंग एक्सपीरियंस) का लाभ देते हुए नियुक्ति की जाए। उनका कहना है कि अतिथि शिक्षकों को शिक्षण अनुभव का लाभ देने के लिए यूजीसी व शिक्षा मंत्रालय को गाइडलाइंस में बदलाव करना होगा क्योंकि वर्तमान नियमों के तहत अतिथि शिक्षकों का शिक्षण अनुभव को वरीयता नहीं दी जाती। उन्होंने अतिथि शिक्षकों को वरीयता दिए जाने की मांग की है और कहा है कि यूजीसी अपनी गाइडलाइंस में बदलाव कर इन्हें एडहॉक शिक्षकों की भांति सुविधाएं मुहैया कराई जाए ताकि सहायक प्रोफेसर की स्थायी नियुक्ति के समय उसे लाभ मिल सकें।

डॉन बनना चाहता था कॉन्स्टेबल किरणपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉकी, दोस्तों के साथ करता था लूटपाट

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में सिपाही किरणपाल की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी उर्फ राधव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। रॉकी ने इंस्टाग्राम पर पिस्टल और चाकू के साथ कई वीडियो अपलोड किए थे। शुक्रवार रात को रॉकी लूटपाट के इरादे से दोस्तों के साथ निकला था और उसने सिपाही को चाकू मार दिया था। पुलिस ने रॉकी के एक साथी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी में शुक्रवार देर रात गश्त के दौरान सिपाही किरणपाल की चाकू मारकर हत्या करने वाले बदमाश रॉकी उर्फ राधव को स्पेशल सेल ने शनिवार रात गोविंदपुरी इलाके में ही मुठभेड़ में मार गिराया। रात 12 बजे सेल की टीम ने जब उसे रोकने की कोशिश की तब उसने पुलिस पार्टी पर पिस्टल से गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसने पांच राउंड फायरिंग की जिनमें एक गोली सब इंस्पेक्टर आदेश के बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। वह बाल-बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी पांच राउंड फायरिंग की जिनमें एक गोली बदमाश की छाती में लग जाने से वह घायल हो गया। उपचार के लिए मजीठिया अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इंस्टाग्राम पर पिस्टल और चाकू का पोस्ट करता था वीडियो

पुलिस का कहना है कि यह डॉन बनना चाहता था। इसने इंस्टाग्राम पर पिस्टल और चाकू लेकर कई सारे वीडियो अपलोड कर रखा है। घटना वाली रात इसी ने सिपाही को चाकू मारा था। शुक्रवार रात रॉकी लूटपाट करने के मकसद से तुषार, दीपक और एक अन्य के साथ स्कूटी से निकला था। सिपाही को चाकू मारने से पहने रॉकी ने दो अन्य लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया था। उसकी कॉल आने के बाद सिपाही किरणपाल और सुनील इलाके में बदमाशों को ढूंढने के लिए निकला था।

आरोपी दीपक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रास्ते से सुनील किसी कारणवश लौटकर पुलिस चौकी आ गया था। किरणपाल द्वारा हंगामे वाले घटनास्थल पर पहुंचने पर जब उसकी बदमाशों से बहस शुरू होने लगी तभी रॉकी ने चाकू निकाल किरणपाल पर वार करना शुरू कर दिया था। बुरी तरह जख्मी करने के बाद चारों सिपाही को मौके पर उन्हें छोड़कर भाग गए थे। दीपक को क्राइम ब्रांच ने शनिवार को ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अब तुषार और एक अन्य की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच तलाश कर रही है।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसरों की होगी नियुक्ति, एलजी की मंजूरी

दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 232 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) की नियुक्ति को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। यूपीएससी द्वारा नियुक्त इन डॉक्टरों की तैनाती एनसीएसएसए के माध्यम से की जाएगी। इनकी नियुक्ति से स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति में हो रही देरी और संविदा के आधार पर नियुक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने से उत्पन्न स्थिति से राहत मिलेगी।

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में उनके रिक्त पदों के अनुसार 232 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की तैनाती को मंजूरी दे दी है। इन डॉक्टरों की नियुक्ति यूपीएससी (UPSC) से की गई थी, जोकि सक्सेना द्वारा उपराज्यपाल का पदभार संभालने के बाद इन पदों को भरने के लिए किए गए ठोस प्रयासों और उनके दिए निर्देशों का परिणाम हैं।

ग्रुप 'ए' अधिकारियों के रूप में नियुक्त इन अधिकारियों की पोस्टिंग एनसीएसएसए (NCSSA) के माध्यम से की गई है और इन्हें लोक नायक, राजा हरीश चंद्र, लाल बहादुर शास्त्री, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों और विभिन्न CDMO कार्यालयों में तैनात किया जाएगा।

उम्मीद है कि इन नियुक्तियों से स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति में पिछले कई वर्षों से हो रही अत्यधिक देरी और आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा एडहॉक तरीके से संविदा के आधार पर नियुक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उससे राहत मिलेगी।

हेड कांस्टेबल की मौत मामले में कोर्ट ने 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के दिए आदेश

परिवहन विशेष न्यूज

अदालत ने कहा बंदूक का यह घाव और साथ ही पांच अन्य घाव प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाए गए। इस प्रकार हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल की मौत हमले और घटना में लगी गोलियों के कारण हुई। रतन लाल तब हल्के बुखार से पीड़ित थे और उनके सहयोगियों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी।

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में 25 आरोपियों के खिलाफ हत्या, आगजनी और डकैती सहित कई आरोप तय करने का आदेश दिया है। इस घटना में पुलिस टीम पर हमले हुए थे, जिसमें हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने यह भी कहा कि संविधान किसी प्रदर्शनकारी को हिंसा, हमला, हत्या या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं देता है। अदालत ने कहा, ₹यह तर्क कि आरोपी अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे, पूरी तरह से गलत है।₹

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रतन लाल को 24 चोटें मिली थी

कोर्ट 27 लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहा था, जिन पर 24 फरवरी को चांद बाग विरोध स्थल पर एक पुलिस टीम पर हमला करने करने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था। अधिकारियों ने उन्हें 24 फरवरी 2020 को मुख्य वजीराबाद सड़क को अवरुद्ध करने से रोकने की कोशिश की थी। 22 नवंबर को पारित अपने 115 पेज के आदेश में अदालत ने कहा कि रतन लाल की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बंदूक का घाव और 24 अन्य बाहरी चोटें दिखाई गईं।

बुखार से पीड़ित होने के बावजूद ड्यूटी पर तैनात थे रतन लाल

अदालत ने कहा, ₹बंदूक का यह घाव और साथ ही पांच अन्य घाव प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाए गए। इस प्रकार, हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल की मौत हमले और घटना में लगी गोलियों के कारण हुई।₹ रतन लाल तब हल्के बुखार से पीड़ित थे और उनके सहयोगियों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। दयालपुर पुलिस स्टेशन सीमा के तहत क्षेत्र में तनाव को देखते हुए वह ड्यूटी के लिए चले गए थे।

घटना में डीसीपी और एसीपी को भी आई थी चोटें

अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन डीसीपी शाहदरा डीसीपी अमित शर्मा और एसीपी गोकलपुरी अनुज कुमार को भीड़ को शांत करने और स्थिति को नियंत्रित करने में मदद की। एक दंगाई भीड़ ने अधिकारियों पर हमला करना शुरू कर दिया तो उन्हें बचाने के दौरान रतन लाल को 24 चोटें आईं, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। लाल के अलावा तत्कालीन डीसीपी और एसीपी को भी गंभीर चोटें आईं, जबकि 50 अन्य पुलिसकर्मी भी घायलों में शामिल थे।

हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा अब होगी पक्की ! पुलिस कॉल करके पूछेगी हालचाल

परिवहन विशेष न्यूज

प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसको लेकर के अब पुलिस ने ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा शुरु की है। जिसके तहत रात में कैब ऑटो में सफर करने वाली महिलाएं 112 पर फोन कर इसकी सुविधा ले सकती हैं। हरियाणा पुलिस के जवान जीपीएस के माध्यम से महिला के ग्रुप को मॉनिटर करेंगे। आपात स्थिति में इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को भेजा जाएगा।

फरीदाबाद। पलवल। पलवल जिले में महिलाओं को सुरक्षित सफर के लिए पुलिस ने ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा शुरु की है। रात में कैब, ऑटो में सफर करने वाली महिलाएं 112 पर फोन कर ट्रिप मॉनिटरिंग की सुविधा ले सकती हैं।

सुविधा लेने के लिए महिला को सबसे पहले 112 पर फोन करना होगा और वेब आधारित फार्म के माध्यम से अपनी यात्रा का पंजीकरण करवाना होगा। सभी जानकारी देने के बाद महिला का ट्रिप शुरू होगा।

पुलिस खुद पूछेगी आपका हालचाल

हरियाणा पुलिस के जवान जीपीएस से महिला के ग्रुप को मॉनिटर करेंगे। हर आधे और एक घंटे में कंट्रोल रूम से फोन कर महिला की कुशलक्षेम भी पूछी जाएगी।

यह जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने बताया कि कैब या ऑटो बीच में रुकता है या फिर रूट में बदलाव होता है, तभी पुलिस महिला को फोन कर जानकारी हासिल करेगी। कुछ भी गलत होने पर सबसे पास स्थित पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को भेजा जाएगा।

महिला पुलिसकर्मी जगह-जगह जाकर कर रही जागरूक

इसके अलावा यात्री द्वारा साझा किए गए आपातकालीन नंबर पर भी संपर्क किया जाएगा। महिला का सफर सुरक्षित पूरा होने के बाद पुलिस फोन कर जानकारी लेगी। इस सुविधा से महिला के स्वजन को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और महिला भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को ट्रिप मॉनिटरिंग की सुविधा के बारे में पलवल पुलिस में तैनात महिला पुलिसकर्मी जगह-जगह जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही है।

पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर कही ये बात

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ट्रिप मॉनिटरिंग की सुविधा होने से दिन हो या रात अब महिलाएं सुरक्षित सफर कर सकेंगी। किसी भी परिवार की बेटी या अन्य कामकाजी महिला सदस्यों की सुरक्षा करना सरकार व पुलिस प्रशासन का परम कर्तव्य है।

हरियाणा पुलिस (Haryana Police) द्वारा चलाई गई इस मुहिम के तहत आपके परिवार की हर महिला तथा बेटी घर से सुरक्षित निकलेगी और जब तक वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती, पुलिस के संपर्क में रहेगी।

हरियाणा की पलवल पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 ठगों को पकड़ा है। इन ठगों को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के सदस्य युवकों को अपने जाल में फंसाकर कंबोडिया में उन्हें ठगी के लिए ट्रेनिंग दिलाते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जिला पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन

गुरुग्राम की हवा में जहर कम नहीं, जानिए स्कूल खुलेंगे या रहेंगे बंद

परिवहन विशेष न्यूज

बढ़ते प्रदूषण के चलते गुरुग्राम में 25 नवंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के गंभीर स्तर को देखते हुए यह निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

फरीदाबाद। बढ़ते प्रदूषण के स्तर और मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्कूल 25 नवंबर को बंद रखे जाएंगे। रविवार को जिला उपायुक्त अजय कुमार ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं कि 25 नवंबर को कक्षा 12वीं तक सभी भौतिक कक्षाएं बंद रखी जाएंगी।

आदेशों में कहा गया है कि जिले के लगभग सभी शहरी और ग्रामीण भागों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर गंभीर श्रेणी में है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में यह निर्णय लिया गया है। स्कूलों में सोमवार को भी ऑनलाइन कक्षाएं ही संचालित की जाएंगी।

स्कूल खुला तो होगी कार्रवाई

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी मुनी राम ने बताया कि डीसी के निर्देश को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सरकारी और प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल को भेज दिए गए हैं। नियमों कापालन करना अनिवार्य है। अगर कोई स्कूल खुला मिलता है तो उनपर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि अगर किसी कारणवश वह बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं दिलाने में समर्थ नहीं हैं तो आसपास के दूसरे बच्चों के मोबाइल फोन पर बच्चों को कक्षाएं दिलाएं, ताकि पढ़ाई बाधित न हो।

ग्वालपहाड़ी में एक्यूआई 300 से अधिक रिकॉर्ड

हवा चलने के बाद भी एक्यूआई बहुत अधिक कम नहीं हुआ है। रविवार सुबह ग्वालपहाड़ी इलाके में 302, टेरीग्राम में 208 एवं विकास सदन में 203 रिकॉर्ड किया गया। दोपहर के दौरान हवा तेज होने पर प्रदूषण का औसतन स्तर 200 से नीचे आ गया था, लेकिन शाम होते-होते फिर बढ़ गया।

ग्रेप-चार अभी भी है लागू

यह हाल तब है जब रविवार को सड़कों पर वाहनों का दबाव काफी कम था। ग्रेप-चार (GRAP 4) लागू होने की वजह से कई प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह बंद हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता राजन शर्मा कहते हैं कि प्रदूषण का स्तर कम तब होगा जब पूरे एनसीआर में नियंत्रण को लेकर एक साथ बेहतर प्रयास किए जाएंगे।

प्रयास पहले से शुरू होने चाहिए

दिक्कत यह है कि प्रयास तब शुरू किए जाते हैं, जब स्थिति गंभीर हो जाती है। जब पता है कि सर्दी के आते ही प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है फिर पहले से ही प्रयास क्यों नहीं किए जाते हैं। बता दें कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद सड़कों व पेड़ों पर पानी का छिड़काव शुरू किया गया है। एंटी स्माग गन की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

गाजियाबाद में अपनों के बीच पहुंच बनाने में सपा-कांग्रेस गठबंधन नाकाम, नतीजा बड़ी हार

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत ने सपा-कांग्रेस गठबंधन की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने संगठन स्तर पर मजबूत आधार तैयार कर मतदाताओं के बीच अपनी पैठ को और गहरा किया। इसी रणनीति के तहत भाजपा प्रत्याशी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। कम मतदान के बावजूद रिकार्ड मतों से गठबंधन प्रत्याशी की हार का नतीजा चौंकाने वाला रहा।

पलवल। गाजियाबाद। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन का उम्मीद से परे बेहद खराब प्रदर्शन रहा। कम मतदान के बावजूद रिकार्ड मतों से गठबंधन प्रत्याशी की हार का नतीजा चौंकाने वाला रहा। इस हार के बाद गठबंधन की चुनावी रणनीति से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। राजनीतिक गलियारे में यह बात पहले से ही तैर रही है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन अपने पारंपरिक वोट बैंक में भी प्रभावी पहुंच बनाने में नाकाम रहा, जिसका नतीजा बड़ी हार के रूप में सामने आया।

गाजियाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए हर बूथ जीतने का मंत्र दिया और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) को साधने के लिए उनकी दुखती नब्ज पर भी हाथ रखा। उनका यह एक प्रयास अपने में ही सिमटा नजर आया।

शहरी मतादाताओं तक पहुंच बनाने में नाकाम

गठबंधन प्रत्याशी शहर के अधिकांश मतदाताओं तक पहुंच बनाने में नाकाम रहा। इसके मुकाबले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो से लेकर तीन बड़े चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सपा और कांग्रेस गठबंधन ने अपनी चुनावी रणनीति में जहां तमाम कमजोरी छोड़ी।

भाजपा ने संगठन स्तर पर बनाई मजबूत पैठ

वहीं, भाजपा ने संगठन के स्तर पर मजबूत आधार तैयार कर मतदाताओं के बीच अपनी पैठ को और गहरा किया। इसी रणनीति के तहत भाजपा प्रत्याशी ने रिकार्ड मतों से जीत दर्ज की। हालांकि, चुनाव परिणाम से पहले राजनीतिक गलियारों में यह बात आम थी कि भाजपा 35 से 40 हजार मतों से जीत दर्ज करेगी, लेकिन यह अंतर 70 हजार तक पहुंचेंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं था।

मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी खिला कमल

बात सिर्फ कुंदरकी विधानसभा सीट की नहीं है। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा का कमल मुस्लिम इलाकों में भी परिणाम के दौरान खिलता नजर आया। मुस्लिम बहुल कैला भट्ठा, इस्लाम नगर और मिर्जापुर आदि में भाजपा प्रत्याशी को उम्मीद से कहीं अधिक वोट मिले। दलित बूथों पर भी भाजपा ने पैठ जमाई, जबकि सपा-कांगेस गठबंधन से यहां सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया था। परिणाम देखें तो इसका कोई लाभ गठबंधन प्रत्याशी को मिलता नजर नहीं आया।

समझ से परे हैं परिणाम : सिंह राज जाटव

सपा-कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी सिंह राज जाटव ने चुनाव परिणाम के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव नतीजे चौंकाने वाले हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में भाजपा कैसे जीत रही है। कुल 507 बूथों में भाजपा इन मुश्किल हालात में 500 बूथों पर जीत गई। जबकि लोगों में भाजपा के प्रति महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़े अपराध को लेकर गुस्सा है।

आलोचना पर दमनात्मक रवैया ठीक नहीं

योगेंद्र योगी

तमिलनाडु में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने राज्य विधानसभा से 43 विपक्षी सदस्यों को निष्कासित कर दिया और उन्हें कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया। जब अंग्रेजी के एक अखबार ने उनके कार्यों की आलोचना करते हुए दो लेख और एक संपादकीय चलाया, तो जयललिता ने जवाब में समाचार पत्र के खिलाफ 17 अलग-अलग आपराधिक मानहानि के मामले दर्ज कराए। जाहिर है कि राजनीतिक दलों के नेताओं के कारनामे उजागर करने पर कानून की चाबुक चलाने में कोई भी पीछे नहीं है'...

सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के नेताओं को आलोचना जरा भी बर्दाश्त नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया पर यदि सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के खिलाफ कुछ लिखा या बोला जाता है, तो उन पर सरकारें दमनात्मक कार्रवाई करने पर उतारू हो जाती हैं। राजनीतिक दल चाहे राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, किसी को आलोचना बर्दाश्त नहीं है। उनका निशाना विपक्ष और मीडिया रहता है। सत्तारूढ़ दलों को आलोचना तभी तक सुहाती है, जब वह विपक्षी दलों की हो। ऐसे में सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए राजनीतिक दलों के नेता सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने में कसर बाकी नहीं रखते। एक फिल्म साबरमती रिपोर्ट को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार के मंत्री गदगद नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीबीसी ने जब गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई तो न सिर्फ उसे प्रतिबंधित कर दिया गया, बल्कि आयकर विभाग ने बीबीसी पर छापे की कार्रवाई की। विक्रांत मैसी की 'दि साबरमती रिपोर्ट' को हरियाणा, छत्तीसगढ़ के साथ ही अब मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ के बाद राजनीतिक महकमों में भी इसकी चर्चा बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फिल्म को देखने के बाद इसकी सराहना की गई। विक्रांत मैसी की फिल्म दि साबरमती रिपोर्ट की केंद्रीय भूमिका वाली यह फिल्म 27 फरवरी, 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर आधारित है। गोधरा स्टेशन के पास खड़ी साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर एस-6 में आग लगा दी गई थी। अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू कारसेवक जिंदा जल गए थे। मरने वालों में 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे। उसके बाद पूरे गुजरात में जो दंगा भडक़ा, वह आजाद भारत के सबसे भयावह दंगों में से एक था। मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब दि साबरमती रिपोर्ट के जरिए बड़े पर्दे पर गोधरा कांड का खौफनाक मंजर दिखा है। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने दि साबरमती रिपोर्ट की प्रशंसा की है। गोधरा में ट्रेन जलाए जाने की भयानक घटना का परिणाम पूरे राज्य में हिंसक दंगों की शक्ल में सामने आया। पूरा गुजरात जल उठा था। केंद्र सरकार ने 2005 में राज्यसभा को बताया था कि दंगों में 254 हिंदुओं और 790 मुसलमानों की जान गई थी। कुल 223 लोग लापता बताए गए थे। हजारों लोग बेघर भी हो गए थे। तत्कालीन मोदी सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया था। उस आयोग में जस्टिस जीटी नानावटी और जस्टिस केजी शाह शामिल थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मारे गए 59 लोगों में से अधिकतर कारसेवक थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए

सरकार ने जस्टिस यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में एक अलग जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग ने मार्च 2006 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में इस घटना को एक दुर्घटना बताया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को असंवैधानिक और अमान्य करार देते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। गोधरा कांड और उसके बाद भडक़े दंगों ने भारत की राजनीति को हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया।

इस मामले में अदालती कार्रवाई जून 2009 से, घटना के आठ साल बाद शुरू हुई। स्पेशल एसआईटी कोर्ट ने 1 मार्च, 2011 को 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें से 11 को मौत की सजा और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने इस मामले में 63 लोगों को बरी भी किया। एसआईटी कोर्ट ने उन आरोपों से सहमति जताई कि यह अनियोजित भीड़ द्वारा की गई घटना नहीं थी, बल्कि इसमें साजिश शामिल थी। 31 दोषियों को भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश, हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। गुजरात सरकार ने बाद में आरोपियों को बरी किए जाने पर सवाल उठाए। जिन्हें दोषी ठहराया गया, उन्होंने भी गुजरात हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने मामले में कुल 31 दोषियों को दोषी ठहराया था और 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के खिलाफ अपील की है, कई दोषियों ने मामले में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। केंद्र सरकार और भाजपा जहां गोधराकांड पर बनी फिल्म को सच सामने लाने वाला बताते हुए तारीफ कर रही हैं, वहीं वर्ष 2023 में गुजरात दंगों पर बीबीसी के बनाए वृत्त चित्र को न सिर्फ प्रतिबंधित कर दिया गया था, बल्कि आयकर विभाग ने बीबीसी के परिसरों में छापे की कार्रवाई की थी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया दि मोदी क्वेश्चन' दो भागों वाली एक श्रृंखला थी। यह जनवरी में यूके में प्रसारित हुई थी। इसमें बताया गया कि 2014 में मोदी के निर्वाचित होने के बाद से, उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने हिंदू-केंद्रित नीतियों को अपनाया है, जिन पर दक्षिणपंथी धार्मिक राष्ट्रवादी एजेंडे के तहत भारत के 200 मिलियन मुसलमानों को निशाना बनाने और उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है, जो भारत को इसकी धर्मनिरपेक्ष नींव से दूर ले जा रहा है। मोदी सरकार की ओर से इस मामले में त्वरित और स्पष्ट प्रतिक्रिया आई। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री में पूर्वाग्रह और निष्पक्षता की कमी तथा औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बीबीसी पर सरकार विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद आयकर विभाग के एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों ने बीबीसी के मुंबई और नई दिल्ली स्थित दफ्तरों पर छापा मारा। इसे उन्होंने सर्वेक्षण बताया। कर चोरी की जांच के तहत फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए और दफ्तरों को सील कर दिया।

इससे जाहिर है कि सत्तारूढ़ दलों के नेताओं को सिर्फ मनमाफिक एजेंडे वाले कार्यक्रम ही सुहाते हैं। इसमें कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जब कभी विपक्षी दलों के खिलाफ हिंसा करवाने के आरोप लगे, तब इसे भाजपा और मीडिया की साजिश करार दिया गया। यही हाल दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय दलों की सरकारों का है। विपक्षी दल और मीडिया जब कभी सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ कोई खुलासा करते हैं, तब उन्होंने प्रताडऩा का सामना करना पड़ता है। इसका प्रमाण यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक कार्टून बनाने पर कार्टूनिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने राज्य विधानसभा से 43 विपक्षी सदस्यों को निष्कासित कर दिया और उन्हें कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया। जब अंग्रेजी के एक अखबार ने उनके कार्यों की आलोचना करते हुए दो लेख और एक संपादकीय चलाया, तो जयललिता ने जवाब में समाचार पत्र के खिलाफ 17 अलग-अलग आपराधिक मानहानि के मामले दर्ज कराए। जाहिर है कि राजनीतिक दलों के नेताओं के कारनामे उजागर करने पर कानून की चाबुक चलाने में कोई भी पीछे नहीं है। सच्चाई की तलाश में किए गए ऐसे प्रयासों पर नेताओं की टेढ़ी नजर रहती है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

आगामी होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर में होंगी दो रिमूवेबल बैटरी

परिवहन विशेष न्यूज

होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक के पहले टीज़र से पता चला है कि इसमें स्विंगआर्म-माउंटेड मोटर के साथ-साथ 7-इंच TFT डिस्प्ले है। नवीनतम टीज़र से पुष्टि होती है कि भारत-स्पेक होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर में बूट में दो रिमूवेबल बैटरी भी होंगी और यह CUV-e इलेक्ट्रिक स्कूटर के समान प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है।

कंपनी की तरफ से स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन होंडा की अंतर्राष्ट्रीय साइट पर CUV-e पर प्रत्येक बैटरी की क्षमता 1.3kWh बताई गई है। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय साइट पर '70 किलोमीटर से अधिक' की रेंज का दावा किया है, लेकिन भारत के लिए पिछले टीज़र ने मानक मोड में यह संख्या 104 किलोमीटर बताई थी।

रिमूवेबल बैटरी एक सराहनीय विशेषता है, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि इससे इस स्कूटर पर बहुत कम बूट स्पेस मिलेगा। टीज़र में जो दिख रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अंडरसीट स्टोरेज स्पेस बैटरी के पीछे एक छोटे से क्यूबी एरिया तक सीमित है। होंडा इस समस्या को फ्रंट एप्रन में निर्मित स्टोरेज बॉक्स के साथ कम कर सकता है, लेकिन यह अभी देखा जाना बाकी है।

प्रदर्शन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय साइट पर अधिकतम आउटपुट 6kW और अधिकतम गति 80kph सूचीबद्ध है। भारत-स्पेक उत्पाद पर संख्याएँ भिन्न हो सकती हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वे एक ही क्षेत्र में होंगी।

भारत के लिए होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर का अनावरण 27 नवंबर को किया जाएगा, जिससे होंडा हमारे बाजार में ईवी लॉन्च करने वाला पहला जापानी ब्रांड बन जाएगा।

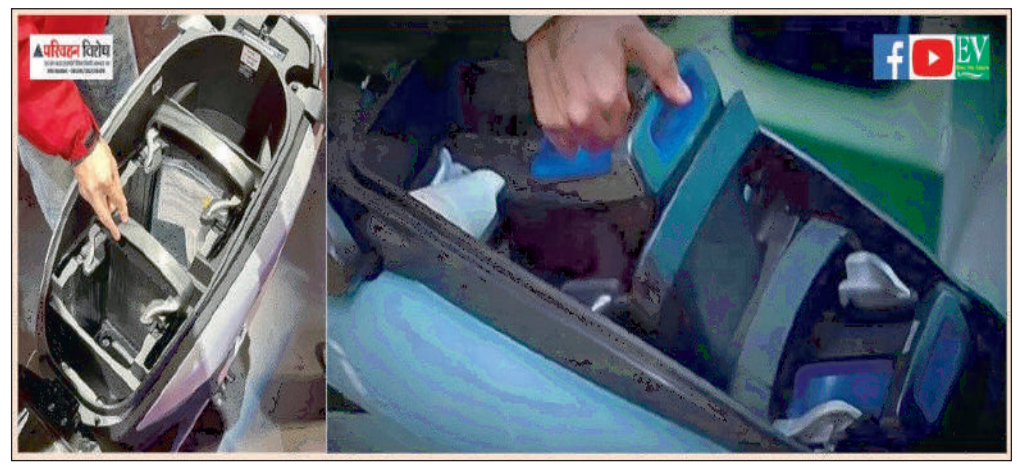

ओला कर रही बड़ी तैयारी, भाविश अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, इन खूबियों के साथ जल्द आएगा नया स्कूटर

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय बाजार में हर महीने सबसे ज्यादा Electric Two Wheeler की बिक्री करने वाली Ola की ओर से जल्द ही नए वाहन को पेश करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले कंपनी के फाउंडर और सीईओ Bhavish Aggarwal ने सोशल मीडिया पर अहम जानकारी साझा की है। भाविष की ओर से किस तरह की जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक दो पहिया निर्माता Ola Electric की ओर से जल्द ही बड़ी घोषणा की जा सकती है। कंपनी के प्रमुख Bhavish Aggarwal की ओर से सोशल मीडिया पर हाल में क्या जानकारी दी गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

ओला कर रही बड़ी तैयारी

ओला इलेक्ट्रिक के प्रमुख Bhavish Aggarwal की ओर से हाल में ही बड़ी जानकारी को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया गया है। भाविश ने शनिवार रात को एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इसमें उन्होंने कुछ फोटो शेयर की हैं और अगले हफ्ते कुछ खास घोषणा की बात कही है।

सोशल मीडिया पर दी यह जानकारी

अपने ट्वीट में भाविश ने तीन फोटो शेयर की हैं। जिनमें एक नए वाहन की जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि बहुत ही रोमांचक काम पर काम चल रहा है! आने वाले सप्ताह में घोषणा की जाएगी!

आएगा नया वाहन

भाविश की ओर से जो फोटो शेयर की गई हैं। उनके मुताबिक की ओर से जल्द ही नए इलेक्ट्रिक वाहन को लाया जा सकता है। फोटो के मुताबिक यह स्कूटर सेगमेंट में लाया जाएगा, जिसका डिजाइन कंपनी के मौजूदा पोर्टफोलियो से पूरी तरह अलग होगा। फोटो के मुताबिक इस नए स्कूटर को कमर्शियल सेगमेंट में लाया जा सकता है।

मिलेगा स्वैपेबल/रिमूवेबल बैटरी का फीचर

कंपनी की ओर से फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाले Electric Scooters में फिक्स्ड बैटरी का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन नए उत्पाद में कंपनी की ओर से स्वैपेबल बैटरी या रिमूवेबल बैटरी का उपयोग किया जाएगा।

क्या होगी खासियत

कंपनी की ओर से नए वाहन के तौर पर लाए जाने वाले नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में कई खासियत दी जा सकती हैं। फोटो के मुताबिक इसका डिजाइन पूरी तरह से मौजूदा S1 से अलग होगा। इसमें नए डिजाइन की एलईडी लाइट दी जाएगी। साथ ही बाइक में मिलने वाले फ्रंट फॉर्क्स का उपयोग इसमें किया जाएगा। साथ ही गिरने पर सुरक्षा के लिए साइड गार्ड को दिया जाएगा। स्कूटर को दो सवारियों के साथ ही सामान ढोने के लिए डिजाइन किया गया है। मौजूदा स्कूटर्स की तरह इसके भी रियर टायर पर हब मोटर को दिया जाएगा। जिससे इसकी कीमत कम रखने में मदद मिलेगी। सीट के नीचे इसमें बैटरी लगाई जाएगी जिसे जरुरत पड़ने पर बाहर भी निकाला जा सकेगा।

क्या होगा फायदा

कंपनी की ओर से अगर रिमूवेबल बैटरी वाले उत्पाद को बाजार में लॉन्च किया जाता है। तो इसका सीधा फायदा ऐसे लोगों को होगा जिनको इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने में लगने वाले समय के कारण परेशानी होती है। रिमूवेबल बैटरी के कारण रेंज कम या खत्म होने पर आसानी से बदला जा सकेगा, जिससे चार्जिंग में लगने वाले समय की बचत हो पाएगी और व्यक्ति बेहद कम समय में लंबी दूरी तक यात्रा कर पाएगा। इसके अलावा बैटरी के रिमूवेबल होने के कारण उसे स्कूटर से निकाल कर घर या ऑफिस में चार्ज करने में भी सुविधा होगी।

हीरो मोटोकॉर्प जीरो मोटरसाइकिल के साथ मिलकर लॉन्च करेगी प्रीमियम ईवी बाइक

परिवहन विशेष न्यूज

कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक हीरो मोटोकॉर्प अपने अमेरिकी पार्टनर जीरो मोटरसाइकिल के साथ मिलकर मिड-साइज़्ड परफॉरमेंस सेगमेंट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल विकसित करने के अंतिम चरण में है।

कैलिफोर्निया स्थित कंपनी जीरो मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और पावरट्रेन में माहिर है। सितंबर 2022 में हीरो मोटोकॉर्प के निदेशक मंडल ने कंपनी में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी थी। साल 2023 में कंपनियों ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक के विकास के लिए सहयोग की घोषणा की थी।

हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निरंजन गुप्ता ने विश्लेषक कॉल में कहा, ₹जहां तक ईवी मोटरसाइकिल का सवाल है, हम इसे जीरो मोटरसाइकिल के साथ साझेदारी में विकसित कर रहे हैं। यह बाइक मध्यम वजन वाले सेगमेंट में आएगी।₹ उन्होंने कहा, ₹यह उन्नत चरण में है। हमने अभी तक इसके लिए समयसीमा की घोषणा नहीं की है, लेकिन हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो बहुत दूर नहीं होगा।₹

निरंजन गुप्ता ने कहा कि बाइक परफॉर्मेंस सेगमेंट में आएगी। कंपनी चालू कैलेंडर वर्ष

में कई मूल्य खंडों में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज का विस्तार भी कर रही है। उन्होंने कहा, ₹जहां तक इलेक्ट्रिक स्कूटर का सवाल है, छह महीने के भीतर हम इसे अधिकांश मूल्य खंडों और ग्राहक खंडों में पूरा कर लेंगे।₹ हीरो मोटोकॉर्प की मौजूदा विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर सीरीज की कीमत फिलहाल 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच है, जिसमें सरकारी सब्सिडी भी शामिल है। कंपनी देश भर के 230 से अधिक शहरों और कस्बों में विडा सीरीज बेचती है। इनमें 400 से अधिक बिक्री टचपॉइंट हैं।

हीरो मोटोकॉर्प को उम्मीद है कि उसके इलेक्ट्रिक उत्पाद वित्त वर्ष 2025-26 तक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना का अनुपालन सुनिश्चित करना। समग्र कारोबारी परिदृश्य पर निरंजन गुप्ता ने कहा, ₹मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक क्षेत्र में है और हम सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से ऑटो क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण के बारे में बहुत आशावादी हैं। इसलिए कुल मिलाकर, मैं कहूंगा कि त्योहारी सीजन के बाद भी त्योहारी उत्साह जारी रहेगा।"

बीते महीने किस बाइक की कितनी रही मांग, टॉप-5 में शामिल हुईं हीरो, होण्डा की ये मोटरसाइकिल

परिवहन विशेष न्यूज

देश में हर महीने लाखों की संख्या में दो पहिया वाहनों की बिक्री होती है। October 2024 के दौरान देश में किस कंपनी की ओर से कितनी Bike Sale की गई हैं। किन बाइक्स को सबसे ज्यादा पसंद (Bike Sale in October 2024) किया गया है। किस कंपनी की कौन सी बाइक Top-5 की लिस्ट में शामिल हुई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में बड़ी संख्या में लोग Bikes चलाना पसंद करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक October 2024 के दौरान बाइक सेगमेंट में कैसा प्रदर्शन रहा है। किस कंपनी की किस बाइक को Top-5 में जगह मिली है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

कितनी हुई बिक्री

भारतीय बाजार में बीते महीने लाखों की संख्या में लोगों ने बाइक्स को खरीदा है। जानकारी के मुताबिक October 2024 के दौरान देशभर में Top-5 बाइक्स की कुल 8885766 यूनिट्स की बिक्री हुई है।

पहले नंबर पर रही Hero Splendor

हीरो मोटोकॉर्प की ओर से भारत में काफी लंबे समय से Hero Splendor बाइक को ऑफर किया जाता है। हर महीने इस बाइक की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। October 2024 के दौरान भी यह बाइक सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बाइक की लिस्ट में पहले पायदान पर रही है। बीते महीने इसकी कुल 391612 यूनिट्स की बिक्री की गई है। पिछले साल इसी अवधि के दौरान इसकी कुल 375886 यूनिट्स को खरीदा गया था।

दूसरे नंबर पर रही Honda Shine

जापानी दो पहिया निर्माता Honda की ओर से Shine को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। बिक्री के मामले में यह बाइक दूसरे नंबर पर रही है। October 2024 के दौरान इस बाइक की कुल 196288 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि पिछले साल इस दौरान इस बाइक की 262316 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

तीसरे नंबर पर आई Hero HF Dlx

हीरो मोटोकॉर्प की HF Dlx बाइक को भी काफी पसंद किया जाता है। बीते महीने के दौरान इस बाइक की कुल 124343 यूनिट्स को खरीदा गया है। जबकि October 2023 के दौरान इसकी 1123827 यूनिट्स को देशभर में खरीदा गया था।

अगले नंबर पर रही Bajaj Pulsar

बजाज की ओर से पल्सर बाइक को कई सेगमेंट में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। बीते महीने के दौरान देशभर में 111834 यूनिट्स को खरीदा गया है। इसके पहले साल 2023 में इसी अवधि के दौरान इस बाइक को 139182 लोगों ने खरीदा था। आंकड़ों के मुताबिक इस बाइक की बिक्री में करीब 20 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई है।

Top-5 में शामिल हुई Bajaj Platina

बजाज की एक और बाइक को Top-5 में जगह मिली है। कंपनी की ओर से एंट्री लेवल सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Bajaj Platina बाइक को भी 61689 लोगों ने खरीदा है। पिछले साल October महीने में इस बाइक को 49774 लोगों ने खरीदा था।

एसबीआई ने बेड़े के विस्तार के लिए अनुकूलित ऋण प्रदान करने के लिए उबर के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

भारत के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने उबर फ्लीट पार्टनर्स के लिए एक अनुकूलित वाहन ऋण उत्पाद पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के राइड-हेलिंग उद्योग को बेहतर बनाने के लिए किफायती वित्तपोषण प्रदान करना और ऋण वितरण को सुव्यवस्थित करना है।

इस सहयोग का उद्देश्य नए और मौजूदा दोनों फ्लीट पार्टनर्स को कम लागत वाले वित्तपोषण विकल्प, कुशल ऋण वितरण प्रक्रियाएँ और उनके संचालन को निर्बाध रूप से बढ़ाने के लिए उपकरण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।

यह साझेदारी एसबीआई के बड़े वित्तीय नेटवर्क और उबर की तकनीकी क्षमताओं को जोड़ती है ताकि बेड़े के मालिकों के लिए परिचालन दक्षता बढ़ाई जा सके, जिससे सुचारू व्यापार विस्तार सुनिश्चित हो सके। यह भारत के तेजी से बढ़ते राइड-हेलिंग क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एसबीआई के प्रबंध निदेशक (खुदरा व्यापार और परिचालन) विनय एम टोंस ने कहा, ₹उबर के साथ हमारी साझेदारी विविध प्रकार के ग्राहकों को अनुकूलित समाधान प्रदान करने पर हमारे फोकस को उजागर करती है। उबर फ्लीट भागीदारों को किफायती वित्तपोषण समाधान प्रदान करके, हम राइड-शेयरिंग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि फ्लीट मालिकों को सफल होने के लिए आवश्यक पूंजी तक पहुँच हो।"

उबेर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने अपने फ्लीट भागीदारों के प्रति कंपनी के समर्पण पर जोर दिया और कहा कि यह साझेदारी अपने फ्लीट भागीदारों के प्रति उबेर की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है और भारत के राइड-शेयरिंग इकोसिस्टम में विकास को बढ़ावा देने के इसके दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि

एसबीआई की अनुकूलित पेशकशों के माध्यम से किफायती ऋण प्रदान करके, कंपनी का लक्ष्य एक सक्षम वातावरण बनाना है जो फ्लीट भागीदारों को प्रभावी ढंग से विस्तार करने और उद्योग के समग्र विकास में योगदान करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है।

इस पहल का उद्देश्य उबेर फ्लीट भागीदारों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, यह सुनिश्चित करके कि उनके पास इष्टतम फ्लीट प्रदर्शन बनाए रखने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुँच है। इससे भारत के राइड-हेलिंग पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है, जो शहरी गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।

हाइब्रिड कार पर नहीं लगता रोड टैक्स, हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा आरटीओ को 6 हफ्ते में रकम लौटाने का दिया आदेश

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में हाइब्रिड गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। जुलाई के पहले खरीदी गई गाड़ियों के जमा टैक्स राशि को वापस किया जाएगा। जुलाई के बाद खरीदे गए हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट मिल रही है, लेकिन इससे पहले खरीदी गई गाड़ियों की स्थिति साफ नहीं थी। कई वाहन स्वामियों की याचिका पर हाई कोर्ट ने जुलाई से पहले खरीदी गई गाड़ियों का भी टैक्स माफ कर पूरी रकम लौटाने के आदेश दिए हैं।

्रशासनिक आदेश के बाद जुलाई से पहले हाइब्रिड वाहन खरीदने वाले इन लोगों को 2.5 लाख रुपये तक का रिफंड मिल सकेगा। गौरतलब है शासन से जुलाई में आदेश जारी के होने के बाद इससे पहले वाहन खरीदने वालों ने टैक्स छूट की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन वाहन स्वामियों का भी टैक्स माफ करने के आदेश दिए हैं।

ग्रेटर नोएडा स्थित बोड़ाकी के अवनेश भाटी ने दिसंबर 2023 में इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड कार खरीदी थी। वह जब इस कार का रजिस्ट्रेशन कराने एआरटीओ ऑफिस पहुंचे तो उनसे रजिस्ट्रेशन के 3.20 लाख रुपये ले लिए गए। अवनेश भाटी को बाद में पता चला कि सरकार ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वीइकल को रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त कर रखा है। इसके बाद वह आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस

करने की अर्जी लेकर पहुंचे, लेकिन अफसरों इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने हाईकोर्ट में रिट दायर की और अब उन्हें जीत मिली है, लेकिन यह समस्या सिर्फ अवनेश भाटी की नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की है। हालांकि हर कोई अवनेश की तरह सामने नहीं आया।

मामले की पैरवी करने वाले वकील मिंटू करन ने बताया कि अवनेश भाटी को जब पता चला कि सरकार ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वीइकल को रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त कर रखा है, तो वह आरटीओ ऑफिस पहुंचे और वहां अफसरों से यह बात कही। उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस करने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद वह इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे।

अदालत में बताया गया कि वर्ष 2023 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बैट्री चलित कारों को रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट दी थी। इसके बाद भी हाइब्रिड गाड़ी का रजिस्ट्रेशन टैक्स वसूलना नियम के खिलाफ है। अदालत ने इसके बाद छह महीने के अंदर टैक्स के रूप में ली गई राशि को वापस करने के आदेश दिए हैं। हालांकि अदालत ने साफ किया है कि इस रकम पर कोई ब्याज राशि देय नहीं होगी, लेकिन अवनेश की इस जीत ने भविष्य में इस तरह की कार लेने वालों के लिए इस जबरन के टैक्स से बचने का रास्ता खोल दिया है।

परिवहन विभाग ने सर्कुलर जारी कर जारी पांच श्रेणियों में से सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स से छूट है। स्ट्रॉंग हाइब्रिड वाहन पहले 50 किलोमीटर तक पेट्रोल और फिर बैटरी से चलते हैं। प्लग इन हाइब्रिड वाहन बैटरी से चलते हैं।

चिरयुवा रहने की ललक में लुटते लोग

विजय गर्ग

बीते दिनों कानपुर शहर में बुजुर्गों को जवान बनाने का झांसा देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई हैरत में डाल देने वाले इस मामले में बुजुर्गों को जवान बनाने के नाम पर पैंतीस करोड़ की ठगी की गई। झांसा देने वाले लोगों ने इजराइली मशीन से जवान कर देने की बात कही थी। वृद्धों को जवान बनाने के नाम पर ठगी लगभग एक साल तक चलती रही। जालसाजी के लिए इजराइल की टाइम मशीन के कमाल और आक्सीजन थेरेपी से जुड़ी मनगढ़ंत बातें बता कर लोगों को भरमाया गया। धोखाधड़ी करने वाले दंपति ने 'नेटवर्क मार्केटिंग' की तर्ज पर पांच सौ से ज्यादा लोगों जोड़ कर उनका 'इलाज' करने की हिमाकत भी कर डाली। एक तरह से जुगाड़ ही कही जा सकने वाली इस मशीन से युवा बनने के फेर में लोगों ने न केवल धन गंवाया, बल्कि सेहत से जुड़ी परेशानियां भी उनके हिस्से आईं। जवान बनाने की प्रक्रिया में कई लोगों के चेहरे जल गए या त्वचा पर सफेद निशान पड़ गए।

दरअसल, लोगों में सदा युवा बने रहने की मनःस्थिति घर करती जा रही है। अब झांसेबाजी की सोची-समझी रणनीति के साथ ही, उम्र की स्वीकार्यता को लेकर लोगों का बदलता मनोविज्ञान जिम्मेदार है। कहना गलत नहीं होगा कि कभी टीवी सिनेमा की दुनिया में चर्चित चेहरों तक सिमटा सौंदर्य और युवा बने रहने का । जुनून अव हर ओर दिख रहा है। सोशल मीडिया की दिखावे की जीवनशैली कहें साधन संपन्न होने के के कारण धन लुटा कर चिर युवा रहने की ललक । शारीरिक सौंदर्य और यौवन को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने की सनक हमारे देश में ही नहीं, दुनियाभर में बढ़ी है। खूबसूरती निखारने वाले सामानों से बाजार अटे पड़े हैं। शारीरिक सौष्ठव के साथ जवान रहने के नुस्खे देने वालों की भीड़ भी बढ़ रही है। आभासी दुनिया से लेकर असली दुनिया तक त्वचा की कसावट और चमक बरकरार रखने के तौर-तरीकों को जानने की ललक रखने वाले कम नहीं। ठग प्रवृत्ति के लोग इसी मानसिकता का फायदा उठाते हैं। तकनीकी संवाद के दौर में अपने अनुभव साझा कर दूसरों को भी प्रेरित करने या जोड़ने की रीत भी चल पड़ी है। कानपुर में युवा बनाने । का झांसा देने वालों ने 'नेटवर्क मार्केटिंग' के माध्यम से ही लोगों का भरोसा जीता था।

यौवन लौटा लाने वाली अविश्वसनीय सी बात पर भरोसा करने के लिए भी ठगों ने उनसे जुड़ने वाले लोगों को लालच दिया। जवान बनने की 'थेरेपी' ले रहे लोगों को 'नेटवर्क मार्केटिंग' से लोगों को जोड़ने पर बाकायदा कमीशन देने का वादा किया गया। इतना नहीं बाजार की रणनीति के मुताबिक ही शुरुआती पेशकश में कम शुल्क रखा गया। लोगों को बताया गया कि एक साल बाद नब्बे हजार वाली योजना तीन लाख रुपए की हो जाएगी। यह वादा भी किया कि कोई व्यक्ति पूरी 'थेरेपी' नहीं लेता है, तो कंपनी एक साल बाद अग्रिम के पूरे पैसे वापस कर देगी। ऐसी बातें जान कर कई लोग जवान बनने की इच्छा से इस जाल में फंसते चले गए। जो लुभावनी बातें दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले किसी उत्पाद के प्रचार में देखने कि मिलती हैं, उनको आधार बना कर इस ठगी के लिए उपभोक्ता भी तैयार किए गए। बीते कुछ वर्षों में सौंदर्य संवर्धन के उत्पाद और युवा बनाए रखने वाली सेवाओं का बाजार देश ही नहीं, दुनियाभर मैं अपने पैर फैला रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि लोग

चमत्कारी बदलावों की उम्मीद तक बांध लेते हैं। यह मनोदशा झांसेबाजी करने वालों के लिए माहौल बना रही है।

चिंता की बात है कि सहज रूप से उम्र की स्वीकार्यता के बजाय उम्र के हर पड़ाव पर ही युवा बने रहने की चाह लोगों को बीमारियों के घेरे में भी ला रही है। लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा स्वयं की देखभाल में लगा रहे हैं। हालांकि इस सजगता का समग्र स्वास्थ्य की देखभाल से कोई लेना-देना नहीं है। बीते दिनों अमेरिकी उद्योगपति ब्रायन जानसन के सदा जवान बने रहने की जिद भी वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनी। चिरयुवा रहने की ठान लेने वाले ब्रायन का दावा है कि उन्होंने अपनी उम्र की चाल उलट दी है। वे सैंतालीस वर्ष की आयु में भी अठारह साल के युवक की तरह दिखने लगे हैं। यह अद्भुत दावा करने की बड़ी वजह उनका 'एज रिवर्स' अनुसंधान है, जिसमें हर साल लगभग सोलह सोलह करोड़ रुपए खर्च होते हैं। निस्संदेह, इसी तरह की मानसिकता के कारण इस विषय पर गहन अध्ययन भी हो रहे हैं। हाल ही में चीनी विज्ञान अकादमी और 'बीजीआई रिसर्च' के वैज्ञानिकों ने बताया है कि शोध के आधार पर ऐसी तकनीक के विकास पर काम हो रहा है, जो उम्र को थामने में मदद कर सकती है। हमारे सामाजिक परिवेश में भी बढ़ती आयु को लेकर असहजता देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों लोगों में उम्रदराज होने का का भय और यौवन को बनाए रखने की यह ललक बढ़ी है? यह उत्कंठा ही युवा बनाने वाले उत्पादों के बाजार को बढ़ावा दे रही है और यह सोच बाजार के मायावी खेल का हथियार बन रही है। झांसेबाजी के नए रास्ते खोल रही है। बावजूद इसके आज उम्र को थाम लेने वाले उत्पादों का बड़ा बाजार बन गया है। समझना आवश्यक है कि बाजार का अपना खेल है, जिसे जानना आमजन की जिम्मेदारी है। यौवन कायम रखने का यह जुनून दूसरे लोगों पर [भी मानसिक दबाव बना रहा है। ऐसा । मनोवैज्ञानिक दबाव जो मन को बीमार करता है। असल में सोशल मीडिया के माध्यम से 'क्लिक' भर में देश-दुनिया तक पहुंचती तस्वीरों ने भी चिर युवा बने रहने की सोच को बढ़ावा दिया है। अध्ययन बताते हैं कि सोशल मीडिया पर सुंदर दिखने की होड़ में हर उम्र के लोग अवसाद का शिकार हो रहे हैं। महिलाएं और युवा तो सौंदर्य संवर्धन के जाल में बुरी तरह फंस रहे हैं।

कुछ साल पहले एक अध्ययन में सामने आया था कि महिलाएं सबसे अधिक चिंतित इस बात से रहती हैं कि वे कैसी दिखती हैं। ब्रिटेन की एक संस्था 'वेट वाचर्स' की ओर से किए गए इस अध्ययन के मुताबिक दिनभर में एक महिला अपने आपको आठ बार कोसती है। हताशा से भरा यह भाव इतना गहरा है कि स्त्रियों को अपने जीवन से जुड़े करीब सभी पहलू कमतर लगने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि कुंठा और तनाव का शिकार बन जाती हैं दिखावटी आभासी संसार ने इस भाव को और पोषित किया है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं। कि तकनीक ने जिस तरह दूरियां घटाई हैं, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बल दिया है। नतीजतन लोग हर कीमत पर युवा बने रहने के जाल में फंस रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में अपनी उम्र की सहज स्वीकार्यता का भाव बना रहे।

प्रदेश में सड़कों का सुधार एवं विस्तार

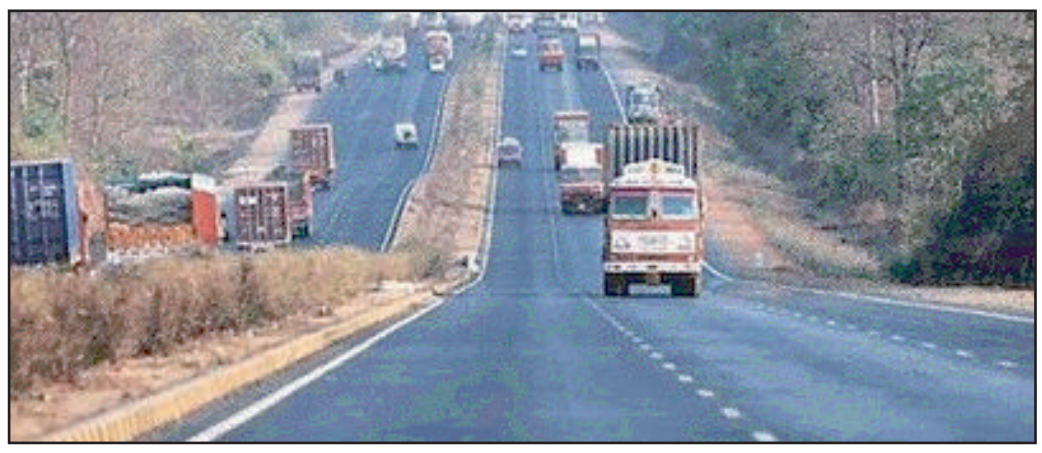

सड़कें न केवल राज्य के विकास की धारा को तेज करती हैं, बल्कि नागरिकों की जीवनशैली और आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार लाती हैं। अच्छी सड़कें रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं, व्यापार को बढ़ावा देती हैं और पर्यटन को भी आकर्षित करती हैं

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, जहां सड़कें ही परिवहन का प्रमुख माध्यम हैं। सड़कें न केवल यातायात के लिए आवश्यक हैं, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभाती हैं। जलमार्ग और रेलवे जैसी सुविधाओं के अभाव में, सडकें हिमाचल के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की रीढ़ के समान हैं। इन सडकों पर भारी वाहनों के साथ-साथ निजी वाहन भी चलते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ते यातायात के कारण, विशेषकर शहरों और कस्बों के पास, ट्रैफिक जाम और यातायात बाधित होने की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्यों के चलते संपर्क सडकों की स्थिति खराब हो रही है। अतः इन सडकों की समय पर मरम्मत और उचित रखरखाव पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इन कार्यों को प्रभावी रूप से अंजाम देने के लिए मजदूरों और तकनीकी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करनी चाहिए। सडक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सडक पर चिह्न (सडक चिन्ह) और सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दुर्घटनाग्रस्त स्थानों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नई सडकों के निर्माण में भारी वाहनों की आवाजाही, जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सडक नेटवर्क के सुधार के लिए लगभग तीन हजार किलोमीटर सडकों के उन्नयन हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की है।

इससे राज्य को कई लाभ होंगे। इसके कार्यान्वयन में ठेकेदारों को उच्च गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्थानीय मजदूरों और तकनीकी विशेषज्ञों को भी इन कार्यों में शामिल करना आवश्यक है ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश में 3500 किलोमीटर नई सडकें बनाने की मंजूरी दी है। इन नई सडकों के निर्माण से प्रदेश के लगभग 300 गांव सडक सुविधा से जुड़ सकेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, 100 से 300 की आबादी वाले गांवों को इस योजना के तहत सडकों की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के पहले चरण में बनीं 800 किलोमीटर सडकों को पक्का करने की भी मंजूरी दी है। पीएमजीएसवाई के चौथे चरण को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक में प्रदेश को यह सौगात मिली है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि विभाग के अधिकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के संपर्क में थे। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों जैसे पांगी, भरमौर, लाहुल-स्पीति और किन्नौर में उन कच्ची सडकों को पक्का करने का काम भी बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा, जोकि प्रदेश के विकास में एक नई गाथा लिखने का काम करेगा।

हिमाचल प्रदेश में लगभग 2000 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है, जिस पर भारी यातायात है। इसलिए संबंधित संस्थाओं को इन सडकों के रखरखाव और मरम्मत के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रदेश में हर साल लगभग 15000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। यदि इस कचरे को सडकों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले तारकोल में मिश्रित किया जाए, तो इससे सडकों की गुणवत्ता में सुधार होगा, खर्च कम होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा, सडकों के निर्माण या मरम्मत के लिए बजट में उचित राशि आवंटित करनी चाहिए। हर साल कुछ सडकों का भूमि पूजन होता है, लेकिन लंबे समय तक काम शुरू नहीं होता, जिससे जनता में असंतोष उत्पन्न होता है। अनुमान के अनुसार, सरकार को एकमुश्त बजट आवंटन करना चाहिए जिससे समय पर कार्य पूरा हो सके। शिमला-मटौर फोरलेन (रानीताल से चील बहल) का उन्नयन कार्य एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इस परियोजना का कुछ हिस्सा पहले ही खोदा जा चुका है और निर्माण कार्य अभी कुछ हिस्सों में चल रहा है, जिससे लोगों को धूल-मिट्टी और अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित संस्था को इस कार्य को निर्धारित मानकों, चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। गुम्मर, देहरियां, पड़ोली-कोहला और बस्दी कोहाला जैसे स्थानों पर सडकों की सतह नीचे चली गई है जिससे स्थानीय रास्तों और संपर्क सडकों को नुकसान हो रहा है। दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को असुविधा हो रही है। अतः संबंधित विभाग को इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अंततः, हिमाचल प्रदेश में सडकों के सुधार और विस्तार के लिए सरकार और जनता के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

अधिक से अधिक जनसहयोग और उचित बजट आवंटन से ही प्रदेश में सडक नेटवर्क को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सकता है। सडकें न केवल राज्य के विकास की धारा को तेज करती हैं, बल्कि नागरिकों की जीवनशैली और आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार लाती हैं। अच्छी सडकें रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं, व्यापार को बढ़ावा देती हैं और पर्यटन को भी आकर्षित करती हैं, जिससे राज्य की समृद्धि में योगदान होता है। इसके अलावा, इन सडकों के माध्यम से आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान हो जाती है, जो कि ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, सडकों का विकास सिर्फ एक बुनियादी ढांचे का सुधार नहीं, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए एक अहम कदम है। सडकें प्रदेश के विकास के लिए एक तरह से नाडियों का काम करती हैं। अगर सडक नेटवर्क बढिया होगा, तो विकास गतिविधियों को तेजी से चलाया जा सकता है। सडकों के माध्यम से विकास की गाड़ी सरपट दौड़ती है, यह एक सर्वमान्य तथ्य है। अतः सडकों का उद्धार होना चाहिए।

● छिलकों की छाबड़ी : नेता जी की नैतिकता'

सभागार ठसाठस भरा हुआ था। तिल धरने को जगह नहीं थी। स्टूडेंट ही स्टूडेंट थे। पुलिस ही पुलिस थी। जितने स्टूडेंट थे उतनी ही पुलिस थी। नेताजी को और क्या चाहिए? भीड़ भी और सुरक्षा भी। जैसे अंधे को चाहिए होती है दो आंखें। नेताजी मुख्य अतिथि थे। उन्हें नैतिकता पर भाषण देना था। स्टूडेंट्स ने यह विषय चुना था और उन्हें इस विषय पर विशेषज्ञ वक्ता की तलाश थी जो नेताजी तक जाकर पूरी हुई। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नेताजी का संबोधन नैतिकता का सागर होता है। इस सागर में डुबकी लगाते ही अनैतिकता छूमंत्र हो जाती है और नैतिकता लहरों में तैरने लगती है। नेताजी सफेद झकाझक कुर्ता-पजामा डालकर आए थे। चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज। हाथ में माइक और दिल में जनता को नैतिकता का असली पाठ पढ़ाने की ललक। नेताजी ने अपने भाषण का श्रीगणेश किया, 'नैतिकता हमारी असली पूंजी है। जो इसके बिना जीवन जीता है, वो जीवन नहीं, एक अधूरा सपना जीता है।' थोड़ा सा गला खंगार कर नेताजी फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में बोले, 'मेरे प्यारे विद्यार्थियो और सुरक्षा कर्मियो, मैं यहां नैतिकता के लिए खड़ा हूं!' सभागार में तालियां गूंजती रही और नेताजी मौका पाकर अपने कुर्ते की जेब में रखी चेकबुक को थपथपाते रहे। नेताजी ने आगे कहा, 'नैतिकता वह गुण है जो हमें इनसान बनाता है।' इतना कहते ही उनकी यादों में वो हर मीटिंग घूम गई, जहां उन्होंने नैतिकता का नाम लेते हुए कई बार योजनाओं को 'संशोधित' करवाया था। नेताजी ने सिर को झटका दिया और अपने मनोभावों को छिपा लिया।

ऐसा करने में उन्हें महारत हासिल है। फिर दार्शनिक अंदाज में नेताजी बोले, 'नैतिकता अब लुप्त होती जा रही है और यह हमारे लिए चिंता का विषय है। मुझे मेरे एक कैबिनेट सहयोगी बता रहे थे कि जंगलों से अब बाघ लुप्त होने लगे हैं। पहाड़ों से ग्लेशियर लुप्त होने लगे हैं। कई अपराधी भी बड़ा अपराध करके लुप्त होने लगे हैं। इस तरह नैतिकता भी अब लुप्त हो रही है और इस बारे हमें बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। हम कैबिनेट में भी इस पर मंथन करेंगे। अभी तक तो हम आर्थिक स्थिति पर ही मंथन कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार खजाना खाली छोड़ कर गई थी और हमने भी सत्ता पाने के लिए बहुत सारे वायदे किए थे। नैतिकता के नाते राजनीति में यह वायदे करने पड़ते हैं। लेकिन खाली खजाना और विपक्ष का सहयोग हमें वायदे पूरे नहीं करने दे रहा। इससे नैतिकता भी खतरे में आ रही है। अगली कैबिनेट में हम नैतिकता को लेकर एक बड़ा कानून बनाएंगे। फिर मंत्रिमंडल की एक सब कमेटी बनाएंगे जो नैतिकता के बारे में समय-समय पर अपनी राय सरकार को देती रहेगी। नैतिकता को लुप्त होने से बचाने के लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी। बेरोजगारों को नौकरी बाद में भी दी जा सकती है। पहले नैतिकता को बचाना जरूरी है और इस सबके लिए स्टूडेंट्स का सहयोग बहुत जरूरी है। कर्मचारियों को तनख्वाह किसी भी तारीख को दी जा सकती है। जरूरी नहीं कि पहली तारीख को ही दी जाए। पांच दस दिन आगे-पीछे भी हो सकते हैं। इसके लिए कर्मचारियों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। पिछले 5 सालों में हमारे परिवार की संपत्ति कई गुणा कैसे बढ़ गई, यह सवाल एक पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे। मैं ऐसे सवालों का जवाब देना चाहता तो दे सकता था, लेकिन मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अभी हमारा फोकस सिर्फ नैतिकता पर है।' सभागार में तालियां बजती रही। नेताजी का संबोधन चलता रहा। मंच पर मौजूद नेताजी के दो सहयोगी आंखों ही आंखों में मंद-मंद मुस्कुराते हुए एक-दूसरे को आंख मारते रहे। सभागार के एक कोने में छुईमुई सी खड़ी नैतिकता मंत्रमुग्ध होकर नेताजी को सुनती रही।

पौधों संचार का विज्ञान

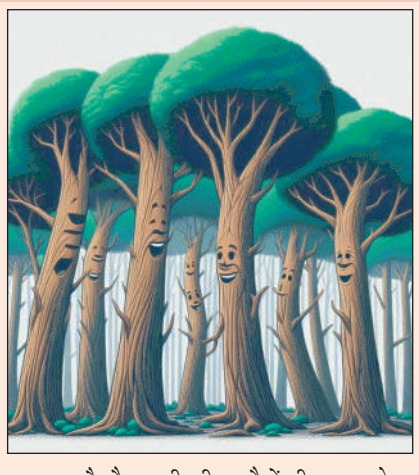

हम जानते हैं कि पक्षी, जानवर और कीड़े-मकौड़े लगातार कुछ ध्वनियाँ निकालकर एक-दूसरे से संवाद करते हैं। लेकिन जब हम पौधों के बारे में सोचते हैं, तो हम कभी भी उनके संचार के बारे में नहीं सोचते हैं। प्रख्यात जीवविज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने अन्यथा सोचा। पौधे भले ही शांत, मूक और एकान्त प्रकार के जीव प्रतीत होते हों लेकिन उनके पास संचार करने का एक जटिल तरीका होता है जो उनके अस्तित्व के लिए दिलचस्प और महत्वपूर्ण है।

किसी भी जीव से अधिक, पौधे संचार के महत्व को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। उनके पास निरंतर संचार का एक पूर्ण, समृद्ध जीवन है। हालाँकि उनके पास आवाज़ नहीं होती, पौधों के पास अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से वे दूसरों को जानकारी प्रदान करते हैं। तो, वो इसे कैसे करते हैं?

रासायनिक चेतावनी

पौधे अक्सर संभावित खतरों के प्रति सतर्क रहते हैं और दूसरों को किसी भी खतरे के बारे में बताकर हमेशा सतर्क रहते हैं। आश्चर्य है कैसे? खतरे में होने पर पौधे हवा में रसायन छोड़ते हैं, जिन्हें वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) के रूप में जाना जाता है, जो आसन्न खतरे के प्रति सतर्क रहने के लिए पड़ोसी पौधों के लिए संकट का काम करता है। जब एक हिरण किसी पौधे को चरता है, तो वह वीओसी छोड़ता है जो पड़ोसी पौधों को शाकाहारी जीवों को दूर रखने के लिए रक्षात्मक यौगिकों या विषाक्त पदार्थों का उत्पादन शुरू करने के लिए सचेत करता है।

एक शोध के मुताबिक, ये वीओसी सिग्नल सिर्फ करीबी पड़ोसियों तक ही सीमित नहीं हैं। यह न केवल हवा में बल्कि मिट्टी में भी यात्रा कर सकता है और काफी दूरी पर पौधों की रक्षा करने में भी मदद करता है। यह पौधों के संचार का सबसे आवश्यक तरीका है जो आसपास के बारे में उनकी समझ और संभावित खतरे या खतरों के प्रति उनकी त्वरित प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

लकड़ी का चौड़ा जाल

जब भी कोई पौधा तनाव का अनुभव करता है - ज्यादातर कीटों के हमले या सूखे के कारण - तो वे तुरंत अपनी जड़ों के माध्यम से दूसरों को रासायनिक संकेत भेजते हैं। यह संकेत अन्य पौधों को अपनी सुरक्षा करने और आगे की स्थिति के लिए तैयार होने में मदद करता है।

जीवविज्ञानियों और वैज्ञानिकों ने पाया कि पौधे माइकोरिज़ल कवक के साथ एक सहजीवी बंधन बनाते हैं जो विभिन्न पौधों की जड़ों को जोड़ता है और इस प्रकार इस कवक नेटवर्क को 'वुड वाइड वेब' नाम दिया गया है। पौधों की जड़ों से कई प्रकार के पौधे-अनुकूल कवक जुड़े होते हैं जो पौधे की जड़ प्रणाली को कवक के तंतु के जाल के साथ विस्तारित करने में मदद करते हैं। यह विस्तृत नेटवर्क पौधों को संकट के समय कवक से प्राप्त पोषक तत्वों को अन्य पौधों तक साझा करने में मदद करता है।

जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है

शोध के अनुसार, जब एक बढ़ते पौधे को अपने संघर्षरत पड़ोसी के बारे में पता चलता है, तो वे अपने पड़ोसी के विकास में सहायता के लिए पोषक तत्व साझा करते हैं। संचार का यह रूप घनी आबादी वाले जंगलों में व्यापक रूप से ध्यान देने योग्य है जहाँ प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों की अत्यधिक आवश्यकता होती है।

पौधे एक साथ काम करके एक लचीला और विश्वसनीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जो दिखाता है कि सहयोग कैसे सभी के अस्तित्व को बढ़ा सकता है और एक के रूप में विकसित हो सकता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि अक्सर पौधे संकट में निकट और दूर के पौधों का समर्थन करने के लिए अपने संसाधनों को प्राथमिकता देते हैं जो समग्र वन स्वास्थ्य में मदद करता है।

जिस तरह से पौधे एक-दूसरे के साथ संवाद करते हैं वह हमारे आस-पास की एक आकर्षक दुनिया को चित्रित करता है जिससे हम बहुत अनजान हैं। रासायनिक संकेत, भूमिगत नेटवर्किंग और सहकारी व्यवहार दिखाते हैं कि ये शांत जीव कितने लचीले और उल्लेखनीय हो सकते हैं। इसलिए, अगली बार जब आप किसी बगीचे या जंगल से गुजरें, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने आस-पास होने वाली मूक बातचीत से अवगत रहें!

सरकारी स्कूलों में डिजिटल विभाजन को पाटना

तेजी से डिजिटल परिवर्तन के युग में, शिक्षा को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। हालाँकि, इस बदलाव ने शिक्षा प्रणाली में स्पष्ट असमानताओं को भी उजागर किया है, विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में, सही ढंग से कहें तो, सरकारी स्कूल अक्सर पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं, जिससे उन उपकरणों तक पहुंच सीमित हो जाती है जो क्रांति ला सकते हैं। बच्चों के लिए सीखने का अनुभव.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) दोनों आधुनिक शिक्षण पद्धतियों की वकालत करते हैं जिनमें डिजिटल पहुंच, व्यक्तिगत शिक्षण परिणाम और शिक्षार्थी स्वायत्तता शामिल है। यह प्रगतिशील दृष्टिकोण छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इसके विकल्प प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना चाहता है। हालाँकि, सरकारी स्कूलों की हकीकत इस आदर्श से कोसों दूर है।

उद्योग जगत का मानना है कि सरकारी स्कूलों के सामने आने वाली प्राथमिक चुनौतियों में से एक संसाधनों की कमी है, खासकर जब डिजिटल बुनियादी ढांचे की बात आती है। जबकि निजी संस्थान तेजी से प्रौद्योगिकी को अपनी कक्षाओं में एकीकृत कर रहे हैं, सरकारी स्कूल अक्सर बुनियादी चीजें भी प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। "कई कक्षाएँ अल्प-सुसज्जित हैं, जिनमें कंप्यूटर, टैबलेट या यहाँ तक कि विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन की बहुत कम या कोई पहुँच नहीं है। यह डिजिटल विभाजन सीखने के अवसरों में एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है, जिससे इन स्कूलों में छात्रों को नुकसान होता है।"

इसके अतिरिक्त, वर्तमान शिक्षा प्रणाली अभी भी माता-पिता और स्कूल अधिकारियों द्वारा संचालित उच्च अंक और रटने पर भारी जोर देती है। यह प्रक्रिया-संचालित फोकस अक्सर समग्र शिक्षा को दरकिनार कर देता है और आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान के महत्व की उपेक्षा करता है। पारंपरिक शिक्षण विधियों से एनईपी 2020 में निर्धारित तरीकों को अपनाने के सरकार के प्रयास में शिक्षकों और छात्रों दोनों के सीखने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। हालाँकि, यह बदलाव कई सरकारी स्कूलों के लिए एक दूर का लक्ष्य बना हुआ है, मुख्यतः संसाधन की कमी के कारण।

व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता

इन चुनौतियों का समाधान करने और सरकारी स्कूलों में एनईपी 2020 के दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने के लिए, नीति को कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित करना आवश्यक है। केवल संसाधन डालना ही पर्याप्त नहीं है; स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध है उसका उपयोग करने और सीखने के लिए एक टिकाऊ, स्केलेबल मॉडल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय भागीदारी और मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है।

एक आशाजनक दृष्टिकोण डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्मों को कम संसाधन वाले वातावरण में अनुकूलित करना है। उदाहरण के लिए, ऑफ़लाइन शिक्षण उपकरण और मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन जिन्हें निरंतर इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता नहीं होती है, खराब कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में अंतर को पाट सकते हैं। स्थानीय संगठनों और शैक्षिक गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करके, स्कूल उन छात्रों तक डिजिटल शिक्षा लाने के लिए इन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, जिनके पास अन्यथा उन तक कभी पहुंच नहीं होती।

विजय गर्ग

सावधानी से खरीदें स्वास्थ्य बीमा, कम प्रीमियम के साथ मिलेंगे ज्यादा फायदे

परिवहन विशेष न्यूज

स्वास्थ्य बीमा बहुत जरूरी है। इस इंश्योरेंस से आप अपने और पूरी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल एक्सपेंस को भी बचा सकते हैं। कई बार महंगे प्रीमियम होने के कारण उपभोक्ता इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। हम इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप कैसे कम प्रीमियम में हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं और इंश्योरेंस लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

नई दिल्ली। स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) खरीदने के दौरान बीमा एजेंट कई प्रकार की जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं देते हैं। ऑनलाइन स्वास्थ्य बीमा खरीदने के दौरान भी जानकारी नहीं होने के कारण ग्राहक अपना प्रीमियम कम नहीं कर पाते हैं। कुछ वर्ष पहले तक स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में मिलने वाली सुविधाओं में बदलाव करने का विकल्प नहीं मिलता था, लेकिन अब यह विकल्प उपलब्ध है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य बीमा उत्पाद की सुविधाओं में बदलाव कर अपना प्रीमियम कम कर सकते हैं।

ऐसे कम कर सकते हैं प्रीमियम

अगर आपको लगता है कि इलाज के दौरान आप सिंगल रूम की जगह डबल रूम में या फिर जनरल वार्ड में रह सकते हैं तो आप सिंगल रूम के फीचर को बदल सकते हैं। इससे आपके प्रीमियम में 5-10 फीसदी तक की कमी आ सकती है। बीमा एजेंट से विचार-विमर्श के बाद आप कई और फीचरों में बदलाव कर प्रीमियम कम कर सकते हैं। फीचर बढ़ाने पर आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा।

अपनी सुविधानुसार तय करें प्रीमियम की अवधि

पहले उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम एक साथ चुकाना पड़ता था। एकसाथ पैसा जाने के कारण कई लोग बीमा खरीदने से चूक जाते थे। लेकिन अब बीमा कंपनियां उपभोक्ताओं की सुविधा के अनुसार प्रीमियम भुगतान की सुविधा दे रही हैं। उपभोक्ता स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम एक साथ देने के बजाए छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर भी दे सकते हैं।

पूरी जानकारी दें

बीमा उत्पाद की खरीदारी के दौरान अपनी पुरानी बीमारी की पूरी जानकारी देनी चाहिए। अन्यथा कई बार इन कारणों से क्लेम खारिज हो जाता है। - बीपी, शुगर या हार्ट संबंधित बीमारी पहले से हैं तो उसकी जानकारी दे देनी चाहिए। इन बीमारियों के लिए तीन साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। मतलब इन बीमारियों से जुड़े इलाज का खर्च वेटिंग पीरियड के बाद कंपनी देगी।

लगातार पांच साल तक इंश्योरेंस जारी रखने के बाद कंपनी किसी बीमारी के क्लेम को खारिज नहीं कर सकती है।

अतिरिक्त प्रीमियम देकर बढ़ाएं कवरेज राशि

पॉलिसी बाजार डॉटकाम के हेल्थ इंश्योरेंस हेड सिद्धार्थ सिंघल का कहना है कि उपभोक्ता स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में दो-तीन हजार रुपये अतिरिक्त देकर अपनी कवरेज राशि को एक करोड़ तक कर सकते हैं। इससे बीमारी के खर्च से पूरी तरह बचा जा सकता है। वित्तीय रूप से सक्षम लोगों को ऐसा जरूर करना चाहिए, क्योंकि गंभीर बीमारी होने पर अस्पताल कम से कम 15-20 लाख रुपये का बिल बना देते हैं। बड़े शहरों में अस्पताल का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक परिवार के पास कम से कम 10 लाख रुपये तक की इलाज सुविधा वाला स्वास्थ्य बीमा होने चाहिए।

चुनावी नतीजों का दिखेगा असर, मार्केट एनालिस्ट ने बताया कौन-से हैं अहम फैक्टर्स

परिवहन विशेष न्यूज

शेयर बाजार में कल से नया कारोबारी हफ्ता शुरू हो जाएगा। इस सप्ताह भी कई फैक्टर्स बाजार की चाल को प्रभावित करेंगे। ऐसे में निवेशकों को इन सभी फैक्टर्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मार्केट एनलिस्ट के अनुसार शनिवार को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर शेयर बाजार पर पड़ेगा। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं...

नई दिल्ली। शेयर बाजार में कल से नवंबर महीना का आखिरी कारोबारी हफ्ता शुरू होगा। यह हफ्ता कई कारणों से जरूरी रहने वाला है। इस हफ्ते बाजार की चाल को कई फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। ऐसे में निवेशकों को हम नीचे बताएंगे कि इस हफ्ते शेयर बाजार के लिए कौन-से फैक्टर्स अहम रहने वाले हैं।

ये फैक्टर्स रहेंगे अहम

मार्केट एनलिस्ट के अनुसार ग्लोबल ट्रेंड्स और एफआईआई ट्रेडिंग एक्टिविटी के अलावा विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी असर स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। शुक्रवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक यानी बीएसई और एनएसई तेजी के साथ बंद हुए थे। इस तेजी ने बाजार को राहत की सांस दी। दरअसल, पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में करेक्शन हो रहा था। इस करेक्शन के कारण दोनों सूचकांक अपने ऑन-टाइम हाई से गिरकर निचले स्तर पर पहुंच गए। आपको बता दें कि पिछले पांच महीनों में यह पहली बार है कि जब एक कारोबारी सत्र में स्टॉक एक्सचेंज 2.5 फीसदी चढ़ा है।

शुक्रवार को सेंसेक्स 1,961.32 अंक या 2.54 फीसदी की बढ़त के साथ 79,117.11 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 557.35 अंक या 2.39 फीसदी की तेजी के साथ 23,907.25 अंक पर बंद हुआ।

इसके आगे संतोष मीना ने कहा कि चुनावी जीत के बाद जहां एक तरफ तेजी की उम्मीद है तो वहीं भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण बाजार को गिरावट का सामना भी करना पड़ सकता है। दरअसल, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही चिंता के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी आई। एफआईआई फ्लो के कारण हाल में ही शेयर बाजार में करेक्शन हुआ है। ऐसे में आगे भी निवेशकों को एफआईआई फ्लो पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।

यूएस डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने और यूएस बॉन्ड यील्ड में तेजी आने के कारण विदेशी निवेशकों ने आउटफ्लो का रूख अपनाया है।

कैसा रहा चुनावी नतीजा

शनिवार को महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई थी। इस चुनाव में महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन को बहुमत मिला। वहीं झारखंड में I.N.D.I.A को बहुमत मिला है।

ये भी **रहेंगे** ट्रिगर्स

ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड और रुपया-डॉलर भी स्टॉक मार्केट का ट्रिगर्स रहेगा। इनके अलावा यूएस के इकोनॉमिक डेटा जैसे जीडीपी ग्रोथ और ग्लोबल ट्रिगर्स भी स्टॉक मार्केट की चाल को काफी प्रभावित करेगा।

पिछले सप्ताह 8 कंपनियों का बढ़ा एम-कैप, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस रहा टॉप गेनर

शेयर बाजार में पिछले हफ्ते शानदार तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को स्टॉक मार्केट के दोनों सूचकांक 2.5 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजार में आई इस तेजी के बाद टॉप-10 वैल्यूएशन कंपनी में से 8 के एम-कैप में तेजी आई है।

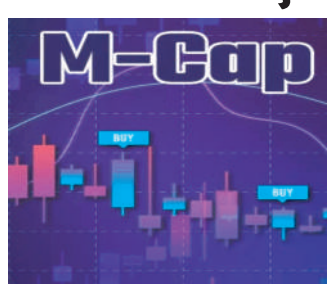

नई दिल्ली। शेयर बाजार की टॉप-10 फर्म में से 8 कंपनियों का एम-कैप पिछले हफ्ते बढ़ा है। इन 8 कंपनियों के एम-कैप में संयुक्त रूप से 1,55,603.45 करोड़ रुपये की बढ़त हुई है। बाजार के टॉप गेनर एचडीएफसी बैंक और टीसीएस रहे। हालांकि, एलआईसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर रहे।

इन फर्म के एम-कैप में आई तेजी

- एचडीएफसी बैंक एम-कैप सबसे ज्यादा बढ़ा है। पिछले सप्ताह कंपनी का बाजार मूल्यांकन 40,392.91 करोड़ रुपये बढ़कर 13,34,418.14 करोड़ रुपये हो गया।
- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का एम-कैप 36,036.15 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,36,149.51 करोड़ रुपये हो गया।
- आईसीआईसीआई बैंक का बाजार मूल्यांकन 16,266.54 करोड़ रुपये बढ़कर 9,01,866.22 करोड़ रुपये हो गया।
- इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 16,189.33 करोड़ रुपये बढ़कर 7,90,151.83 करोड़ रुपये हो गया है।
- हिंदुस्तान यूनिलीवर का एमकैप 13,239.95 करोड़ रुपये की बढ़त के साथ 5,74,569.05 करोड़ रुपये हो गया।
- आईटीसी का बाजार पूंजीकरण 11,508.91 करोड़ रुपये बढ़कर 5,94,272.93 करोड़ रुपये हो गया।
- भारती एयरटेल का एमकैप 11,260.11 करोड़ रुपये बढ़कर 8,94,068.84 करोड़ रुपये हो गया।
- भारतीय स्टेट बैंक का बाजार मूल्यांकन 10,709.55 करोड़ रुपये बढ़कर 7,28,293.62 करोड़ रुपये हो गया।

पिछले सप्ताह केवल एलआईसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के एम-कैप में गिरावट आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एम-कैप 2,368.16 करोड़ रुपये घटकर 17,13,130.75 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, एलआईसी का बाजार पूंजीकरण 11,954.24 करोड़ रुपये घटकर 5,62,545.30 करोड़ रुपये रह गया है।

क्या है टॉप-10 फर्म की रैंकिंग

एम-कैप में आई गिरावट के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर बाजार की टॉप फर्म है। इसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी आते हैं।

शेयर बाजार का स्तर

शुक्रवार को सेंसेक्स 1,961.32 अंक या 2.54 फीसदी की चढ़कर 79,117.11 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 557.35 अंक या 2.39 फीसदी की तेजी के साथ 23,907.25 अंक पर बंद हुआ।

आयकर विभाग ने दी करदाता को सलाह, आईटीआर भरने से पहले जरूर रिव्यू करें ये चीज

परिवहन विशेष न्यूज

सेंटर्ल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने करदाता को सलाह दिया है कि वह आईटीआर सबमिट करने से पहले एक बार अपने फॉरन इनकम और एसेट को जरूर रिव्यू करें। दरअसल इसको लेकर काफी भ्रम फैल रहा था। करदाता के बीच इस भ्रम को खत्म करने के लिए आयकर विभाग ने करदाता को अपने स्पेशन संस्करण संवाद में विदेशी आय और संपत्ति के नियमों की जनकारी दी।..

नई दिल्ली। सेंटर्ल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने सभी करदाता को सलाह दी है कि वह इनटैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने से पहले अपने फॉरेन इनकम और एसेट को जरूर रिव्यू और फिर उस आधार पर ही जानकारी भरें।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्पेशल एडिशन 'Samvad' में टैक्सपेयर्स को यह सलाह दी गई। यह अभियान टैक्सपेयर को जागरूक करने के लिए शुरू की गई है। इस अभियान के अनुसाप टैक्सपेयर को फॉरेन इनकम और एसेट को ध्यान से रिव्यू करने के बाद ही उसकी जानकारी आईटीआर में देनी चाहिए।

सत्र के दौरान, सीबीडीटी के आयुक्त (जांच) शशि भूषण शुक्ला ने बताया के सभी भारतीय नागरिक को फॉरेन एसेट्स जिसमें बैंक अकाउंट, रियल स्टेट, शेयर, इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी देनी होती है जिसके वह मालिक हैं।

इसके आगे उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म ₹Foreign Assets and Income₹ में स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दिया है। इस गाइड की मदद से वह फॉरेन इनकम और संपत्ति की जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह नियमनिवासी करदाताओं पर लागू होता है। इसकी जानकारी आयकर अधिनियम की धारा 6 में दिया गया है।

शुक्ला ने स्पष्ट किया कि नियमों के मुताबिक रेसिडेंट टैक्सपेयर वह हैं जो पिछले वर्ष के दौरान कम से कम 182 दिनों तक भारत में रहा हो या जो पिछले चार वर्षों के दौरान 365 दिनों तक भारत में रहा हो। अगर कोई करदाता इन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उसे अनिवासी माना जाएगा। अनिवासी को विदेशी आय और संपत्ति की घोषणा करने की जरूरत नहीं है।

दूर हुई कन्फ्यूजन

कई बार टैक्सपेयर जिनके पास कोई विदेशी आय या संपत्ति नहीं होती है, लेकिन वह फिर भी इसकी जानकारी आईटीआर में देते हैं। ऐसे में फैल रहे भ्रम को खत्म करने के लिए शुक्ला ने पूरी तरह से स्पष्ट किया कि विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी किन करदाताओं को करनी है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी करदाता ने विदेश में कोई संपत्ति खरीदी है और उससे कोई इनकम नहीं आ रही है तब भी उस संपत्ति की जानकारी आईटीआर में देनी चाहिए।

अगर कोई एनआरआई भारत में आता है और उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है तो उन्हें भी अपने विदेश संपत्ति और आय की जानकारी देनी होगी। यह नियम उन विदेश नागरिक पर भी लागू होती है जब वह भारत के नागरिक बन जाते हैं।

कल फोकस में रहेगा शेयर, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आया था बड़ा अपडेट

परिवहन विशेष न्यूज

आरवीएनएल शेयर सोमवार को निवेशकों की नजर रेलवे सेक्टर की कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (Rail Vikas Nigam Ltd.-RVNL) पर बनी रहेगी। दरअसल शुक्रवार को कंपनी ने बताया कि उसे पूर्वी रेलवे की तरफ से इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है। इस खबर के बाद एक्सपर्ट का मानना है कि सोमवार को शेयर आ सकती है। शुक्रवार को शेयर 420.40 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था।

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

नई दिल्ली। शेयर बाजार में कल से नया कारोबारी हफ्ता शुरू होगा। यह सप्ताह नवंबर का आखिरी कारोबारी सप्ताह है। सप्ताह के पहले दिन ही शेयर बाजार के निवेशकों का फोकस रेलवे सेक्टर की कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (Rail Vikas Nigam Ltd.-RVNL) के शेयर (RVNL Share) पर बनी रहेगी।

शुक्रवार को बाजार होने के बाद कंपनी ने अहम जानकारी दी थी। इस जानकारी के बाद निवेशकों को उम्मीद है कि सोमवार को कंपनी के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर सकता है। कंपनी ने बताया कि उसे पूर्वी रेलवे से इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है।

कंपनी को मिला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट

RVNL ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे पूर्वी रेलवे से एक स्वीकृति पत्र (LoA) हासिल मिला। इस पत्र के अनुसार RVNL को इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट में भूमि कार्य, पुल निर्माण और रेलवे ट्रैक बिछाने, लेवल क्रॉसिंग आदि काम शामिल है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 837.67 करोड़ रुपये है। कंपनी को कालीपहाड़ी और प्रधानखुता के बीच काम करना है। यह मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे बीजी लाइन है।

कंपनी का यह प्रोजेक्ट ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी ने SCPL के साथ जीवी किया है। इस जीवी में RVNL के पास 74 फीसदी और SCPL के पास 26 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी ने कहा कि उसे यह प्रोजेक्ट घरेलू संस्था के जरिए मिला है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 36 महीने का समय लग सकता है।

कैसी है कंपनी की वित्तीय स्थिति

RVNL द्वारा जारी हुए दूसरी तिमाही नतीजे (RVNL Q2 Result) के अनुसार कंपनी का साल-दर-साल के हिसाब से नेट प्रॉफिट 27 फीसदी गिरकर 286.9 करोड़ रुपये रहा। इस वजह सं कंपनी के ऑपरेशनल मार्जिन और इनकम में भी गिरावट आई। सितंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल इनकम 1.2 फीसदी घटकर 4,855 करोड़ रुपये रहा। वहीं, EBITDA भी 9 फीसदी गिरकर 271.5 करोड़ रुपये रहा।

कैसा है शेयर का हाल

22 नवंबर 2024 (शुक्रवार) को कंपनी के शेयर बीएसई पर 1.25 रुपये या 0.30 फीसदी की गिरावट के साथ 420.40 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। BSE Analytics के अनुसार पिछले पांच सत्रों में कंपनी का स्टॉक 1.98 फीसदी चढ़ा। एक साल में कंपनी के शेयर में 19.83 फीसदी की तेजी आई। वहीं बीते छह महीने में कंपनी के स्टॉक में 6.60 फीसदी की तेजी आई।

विदेशी निवेशकों ने अपनाई निकासी की रणनीति, नवंबर में बेचे 22,420 करोड़ रुपये की इक्विटी

नई दिल्ली। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के एलान के बाद विदेशी निवेशक (FPI) भारतीय शेयर बाजार से निकासी कर रहे थे। इस निकासी के कारण शेयर बाजार (Share Market) में भारी बिकवाली देखने को मिली। अब नवंबर महीने में एफपीआई आउटफ्लो का डेटा जारी हो गया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार नवंबर में अभी तक विदेशी निवेशकों ने 22,420 करोड़ रुपये तक की इक्विटी बेची। विदेशी निवेशक शेयर बाजार से निकासी करके चीन में निवेश कर रहे हैं। यूएस डॉलर (US Dollar) के मजबूत होने के कारण भी विदेशी निवेशक निकासी कर रहे हैं। नवंबर में हुए आउटफ्लो के बाद एफपीआई (FPI Data November 2024) ने 2024 में कुल 15,827 करोड़ रुपये की निकासी की है।

भारत में फोरविस मजार्स के वित्तीय सलाहकार भागीदार अखिल पुरी के अनुसार शेयर बाजार में एफपीआई इनफ्लो थोड़े समय के बाद चालू हो सकती है। जनवरी से पहले एफपीआई इनफ्लो जारी होने की उम्मीद है। अभी एफपीआई आउटफ्लो ने बाजार की चाल को सीमित कर दिया है।

अभी तक कितनी हुई निकासी

एफपीआई डेटा के अनुसार नवंबर में अभी तक विदेशी निवेशकों ने 22,420 करोड़ रुपये की निकासी की है। पिछले महीने में अक्टूबर में 94,017 करोड़ रुपये की निकासी की थी। यह इस साल का अभी तक सबसे ज्यादा आउटफ्लो है। अक्टूबर 2024 से पहले विदेशी निवेशकों ने मार्च 2020 में सबसे ज्यादा निकासी की थी। मार्च 2020 में एफपीआई ने 61,973 करोड़ रुपये विड्रॉल किया है। सितंबर 2024 में विदेशी निवेशकों ने 57,724 करोड़ रुपये का इनफ्लो किया था, जो 9-महीने का उच्चतम स्तर है।

एफपीआई ने क्यों अपनाई आउटफ्लो रणनीति

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार के अनुसार एफपीआई ने अक्टूबर से निकासी की रणनीति तीन कारण की वजह से अपनाई है। यह तीन वजह- भारत में उच्च वैल्यूएशन, निराशाजनक तिमाही नतीजे और ट्रंप ट्रेड है।

एफपीआई ने इस समीक्षाधीन अवधि के दौरान डेट मार्केट में 42 करोड़ रुपये और वीआरआर में 362 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस साल अब तक एफपीआई ने डेट मार्केट में 1.06 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है।

नवंबर में जारी है निकासी का रूख, विदेशी निवेशकों ने निकाले 26,533 करोड़ रुपये

एफपीआई डेटा विदेशी निवेशकों ने निकासी का रुख अपनाया हुआ है। एफपीआई ने अक्टूबर महीने में निकासी किया था। अब वह नवंबर महीने में भी निकासी कर रहे हैं। एफपीआई आउटफ्लो का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है। एफपीआई डेटा के अनुसार 22 नवंबर तक विदेशी निवेशकों ने 26533 करोड़ रुपये की निकासी की है। पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली। शेयर बाजार में आई गिरावट की वजह एफपीआई आउटफ्लो भी है। अक्टूबर महीने से विदेशी निवेशकों ने निकासी का रूख अपनाया। नवंबर में भी विदेशी निवेशकों द्वारा आउटफ्लो जारी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार नवंबर में विदेशी निवेशकों ने 26,533 करोड़ रुपये तक की निकासी की है।

एफपीआई आउटफ्लो के कारण भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट आई है। भारतीय शेयर बाजार से निकासी करके विदेशी निवेशक चीन के बाजार में निवेश कर रहे हैं।

अक्टूबर में एफपीआई ने आउटफ्लो ही किया है। इस महीने निवेशकों ने 94,017 करोड़ रुपये की निकासी की थी। इस निकासी के बाद अब साल 2024 में नेट बेसिस पर कुल एफपीआई आउटफ्लो 19,940 करोड़ रुपये है।

एफपीआई आउटफ्लो डेटा

एपीआई डेटा के अनुसार 22 नवंबर 2024 तक एफपीआई ने 26,533 करोड़ रुपये की निकासी की है। वहीं, अक्टूबर में कुल 94,017 करोड़ रुपये की निकासी हुई। यह आउटफ्लो के आधार पर सबसे खराब महीना रहा है। सितंबर 2024 में एफपीआई ने 57,724 करोड़ रुपये का इनफ्लो किया था जो 9-महीने के उच्चतम स्तर पर है।

विदेशी निवेशकों ने निराशाजनक तिमाही नतीजे आने के कारण आउटफ्लो कर रहे हैं। इसके अलावा 'Sell India, Buy China' खत्म हो गया है। अब 'the Trump trade' शुरू हुआ है। इसके बाद यूएस की वैल्यूएशन में शानदार तेजी आई।

एफपीआई आउटफ्लो होने के बावजूद विदेशी निवेशक आईटी स्टॉक को खरीद रहे हैं। वह बैंकिंग स्टॉक को बेच रहे हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली से स्टॉक मार्केट में करेक्शन हो रही थी, लेकिन इस स्थिति में घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीद ने बाजार को सपोर्ट किया है।

एफपीआई ने 22 नवंबर तक डेट लिमिट से 1,110 करोड़ रुपये की निकासी की है। वहीं, VRR (Voluntary Retention Route) में 872 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस साल में अभी तक एफपीआई ने 1.05 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है।

न हिंदुत्व न दल और न नेता ,जीती तो केवल लाड़ली बहना

(डॉ.मुकेश "कबीर"-विनायक फीचर्स)

महाराष्ट्र और झारखंड के रिज़ल्ट और इसके पहले हरियाणा के रिजल्ट से यह बात साफ हो गई कि अब देश में मुफ्त की योजनाएं ही चुनाव का आधार बन चुकी हैं । फिर चाहे मुफ्त बिजली पानी हो या फिर लाडली बहना जैसी योजनाओं द्वारा पैसा बांटना हो,लोग अब इसी के आधार पर वोट देते हैं। महाराष्ट्र के बारे में कहा यह जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत हुई लेकिन झारखंड या अन्य राज्यों के परिणाम देखें तो हिंदुत्व कहीं दिखाई नहीं दिया,बल्कि जहां जिस जाति की संख्या ज्यादा थी या जिसकी सरकार थी उनके कैंडिडेट ही जीते। बंगाल में पूरी छह सीट ममता की पार्टी जीती तो वायनाड में प्रियंका को बड़ी जीत मिली,कुल मिलाकर राज्य सरकार का प्रभाव दिखाई दिया। वैसे महाराष्ट्र की बात करें तो कहा जा रहा है कि वहां हिंदुत्व की सुनामी थी लेकिन यदि वहां हिंदुत्व होता तो लाडली बहना योजना शुरू नहीं करना पड़ती। महाराष्ट्र की सरकार और स्थानीय नेता अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व कभी चुनाव जिताऊ मुद्दा नहीं रहा,यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ केरबटेंगे तो कटेंगेर का सबसे पहले विरोध महायुति के नेताओं ने ही किया। अजीत पंवार और पंकजा मुंडे दोनों ने इस नारे का विरोध किया। दोनों का कहना था कि महाराष्ट्र में यह नारा व्यर्थ है । शिंदे भी पहले ही समझ चुके थे इसीलिए उन्होंने लाडली बहना जैसी लुभावनी योजना शुरू की और सिर्फ शुरू ही नहीं की बल्कि पांच महीने का एडवांस भी दे दिया,हर घर में साढ़े सात हजार मुफ्त में आए तो महिलाओं को महायुति की सरकार भाने लगी वरना लाडली बहना से पहले जितने भी सर्वे आए थे उनमें महायुति की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी । यदि स्थिति अच्छी होती तो कम से कम महाराष्ट्र में तो लाडली योजना लांच नहीं की जाती लेकिन यह योजना शुरू की गई और एक महीने बाद ही फिजा बदल गई । खासकर जो लेबर क्लास की महिलाएं हैं,जो घरों में काम करने वाली मौशीयां हैं उनमें जबरजस्त उत्साह देखा गया और फिर बीजेपी यह नरेटिव सेट करने में भी सफल रही की यदि महायुति की सरकार चली गई तो आघाड़ी इस योजना को बंद कर देगी,जबकि आघाड़ी ने इस योजना का पैसा डबल करने का वादा किया था । यहां महिलाओं का भरोसा महायुति के साथ रहा । बहरहाल हिंदुत्व का नारा यहां नहीं चला,यदि हिंदुत्व का नारा चलता तो उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीटें राज ठाकरे की आना चाहिए थी क्योंकि राज ठाकरे बीजेपी के साथ थे और उनके भाषणों में भी हिंदुत्व और राष्ट्र के मुद्दे ज्यादा थे साथ ही वे मुस्लिमों पर कड़े शाब्दिक प्रहार भी कर रहे थे,बिल्कुल बाला साहेब की ही तरह लेकिन उनके सवा सौ उम्मीदवारों में से एक भी नहीं जीता । उनके खुद के बेटे भी नहीं जीत सके। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राज ठाकरे लगातार लाडली बहना योजना का विरोध कर रहे थे । शायद इसीलिए उनकी सभा में आने वाली भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो सकी। हालांकि राज ठाकरे की हार पर अभी मीडिया में चर्चा ज्यादा नहीं है बल्कि सारे देश में चर्चा सिर्फ उद्धव की हार ही हो रही है। खासकर हिंदूवादी पार्टियों के समर्थक उद्धव की हार का कारण बीजेपी का साथ छोड़ना ही बता रहे हैं। वैसे यह भी पूरी तरह सच नहीं है क्योंकि उद्धव की इमेज महाराष्ट्र में आज भी हिंदूवादी नेता की है। उनके बारे में नरेटिव सेट किया जा रहा था कि उन्होंने अपनी हिंदू वादी विचारधारा छोड़ दी है। लोकसभा में वक्फ बिल के मुद्दे पर बॉयकॉट करने से ही उद्धव के मुस्लिम वोटर्स नाराज हो गए थे और मातोश्री के

सामने धरना प्रदर्शन भी करने लगे।मातोश्री (बाल ठाकरे का घर) के सामने इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम्स पहली बार देखे गए ,खैर उद्धव को बॉयकॉट का नुकसान हुआ वरना मुस्लिम वोट उनको मिलते तो कुछ सीटें ज्यादा बढ़ जाती । यह सॉफ्ट हिंदुत्व ही उद्धव को भारी पड़ा। महाराष्ट्र के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया ने तो इसको हिंदुत्व की जीत मान लिया है लेकिन झारखंड में हिंदुत्व क्यों नहीं चला जबकि वहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर हिंदुत्व की बात की थी ।शर्मा तो मिशनरी और मदरसों के खिलाफ खूब बोले थे और हिंदुओं को एकजुट होकर वोट करने की अपील की थी, लेकिन वहां भी हेमंत सोरेन की मईयां सम्मान योजना ने शायद सोरेन को बचा लिया । सोरेन ने लाड़ली बहना की ही तरह मईयां सम्मान योजना झारखंड में पहले ही शुरू कर दी थी। महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं बीजेपी का ट्रंप कार्ड रही है लेकिन यह कार्ड सोरेन पहले ही चल चुके तो बीजेपी के पास कुछ रहा नहीं लुभाने के लिए वरना हरियाणा में भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा और प्रचार किया था इसलिए आखिरी के तीन महीने में बीजेपी का माहौल तेजी से बन गया जबकि पहले हरियाणा में भी स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही थी ।लगभग यही हाल मध्यप्रदेश का था लेकिन मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से ठीक पहले लाडली बहना योजना शुरू की तो बीजेपी की बंपर वापसी हुई और नतीजे बिल्कुल वैसे ही एकतरफा निकले जैसे आज महाराष्ट्र में निकले हैं। बहरहाल हार जीत तो चुनाव का एक हिस्सा है और उसके बाद समीक्षा भी एक परंपरा है । जिसमें सब अपनी अपनी भड़ास निकालते हैं और अलग अलग कारण गिनाए जाते हैं लेकिन एक बात पक्की है कि जीत हार के कारण जो भी हों लेकिन यह मुफ्त की योजनाएं अब हमारे चुनाव का हिस्सा बन चुकी हैं । यह देशहित में तो नहीं कही जा सकतीं लेकिन राजनीतिक दलों के लिए सौ फीसदी फायदे का सौदा है। इसलिए सारी पार्टियां आजकल इसी फार्मूले पर काम कर रही हैं। यह बात अलग है कि इसी मुद्दे पर वो एक दूसरे की आलोचना भी करती हैं । जब केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की योजनाएं लाए तो बीजेपी ने काफी आलोचना की लेकिन अब बीजेपी ने भी ऐसी ही कई योजनाएं शुरू कर दी हैं। उनको भी समझ आ गया है कि जनता को क्या चाहिए इसलिए बीजेपी ने पहले मध्यप्रदेश फिर हरियाणा और अब महाराष्ट्र लाड़ली बहना के सहारे जीता और सोरेन ने लाड़ली बहना के भरोसे झारखंड में सत्ता में वापसी की। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इतना पैसा लाएंगे कहां से ? महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए दिए गए इनकी रिकवरी कैसे होगी,क्योंकि जिन राज्यों में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं वहां की सरकारें परेशान हैं। पैसा देने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए और आखिर में पैसा जनता से ही वसूला जाता है,लाड़ली बहना के लिए लाड़ले भाईयों की जेब खाली की जाती है । मध्यप्रदेश में बीस साल पहले ही जनता इसका दुष्परिणाम भुगत चुकी है,जब दिग्विजय सिंह ने पहले तो बिजली मुफ्त की थी लेकिन बाद में बिजली के बिल इतने महंगे कर दिए कि बिजली के कारण ही दिग्विजय की राजनीति फ्यूज हो गई और फिर कभी नहीं चमके। अब ऐसी योजनाओं का बंद होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है क्योंकि अब चुनाव जीतने का ट्रंप कार्ड ऐसी योजनाएं ही हैं। वर्तमान चुनाव परिणामों से तो अब ऐसा लगता है कि जिस स्टेट में जिसकी सरकार है वही बार बार रिपीट होगी क्योंकि मुफ्त की योजनाओं की चाबी तो सत्ताधारी दल के पास ही होती है। फिर चाहे वह दिल्ली में आम आदमी हो या महाराष्ट्र में खास आदमी । बहरहाल जो जीते उनको बधाई,आखिर जो जीते वही तो सिकंदर हैं,जो हारा वो अब आलोचना कर सकता है पांच साल तक...(विनायक फीचर्स)

बालमन का सुन्दर विश्लेषण करती है बाल-प्रज्ञान

सन 1989 में हरियाणा में जन्मे डॉ. सत्यवान सौरभ बालसाहित्य के एक सुपरिचित हस्ताक्षर हैं। साहित्यकार, पत्रकार और अनुवादक डॉ. सत्यवान सौरभ ने बच्चों के साथ ही बड़ों के लिए भी विपुल साहित्य सर्जन किया है। बाल कविता की पुस्तकों के साथ ही प्रौढ़ साहित्य में दोहा, कथा, कविता, अनुवाद, रूपान्तर, सम्पादन की कई कृतियों का सर्जन कर उन्होंने हिन्दी साहित्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। बीस वर्षों से स्वतंत्र रूप से लेखन कर साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं।

बाल प्रज्ञान, बाल साहित्यकार डॉ. सत्यवान सौरभ जी की बाल कविताओं का सुन्दर संग्रह है। कवि की सभी रचनाएँ बाल मनोविज्ञान के अनुरूप हैं और बच्चों के मन का सुन्दर विश्लेषण करती हैं। बच्चों को बरसात के पानी में भीगना बहुत भाता है। बरसात की रिमझिम फुहारों में वे गर्मी की सारी तपन को भूलकर झूम उठते हैं। 'रिमझिम-रिमझिम बारिश आई' कविता में कवि बरसात के साथ बच्चों के इसी सम्बन्ध को अभिव्यक्त करते हुए कहता है-

"चली हवाएँ करती सन-सन।
झूम उठे हैं सबके तन-मन॥
बादल प्यारे गीत सुनाते।
बच्चे मिलकर धूम मचाते॥
जीव जन्तु और खेत हर्षाए।
पंछियों ने पँख फैलाए॥

इस बालकविता संग्रह की पहली कविता 'बने संतान आदर्श हमारी' में कवि ने किसी भी माता-पिता की होने वाली संतान का सुन्दर चित्रण किया है। बालमन के स्तर पर उतरकर कवि ने भावना को सहज रूप से मुखरित करते हुए कहा है-

" बने संतान आदर्श हमारी, वह बातें सिखला दूँ मैं।
सोच रहा हूँ जो बच्चा आये, उसका रूप, गुण सुना दूँ मैं॥
बाल घुंघराले, बदन गठीला, चाल, ढाल में तेज भरा हो।
मन शीतल हो ज्यों चंद्र-सा, ओज सूर्य-सा रूप धरा हो॥
मन भाये नक्स, नैन हो, बातें दिल की बता दूँ मैं।
बने संतान आदर्श हमारी, वह बातें सिखला दूँ मैं॥"

'नानी' इस संग्रह की लम्बी कविता है जिसमें बाल सुलभ शरारतों का यथार्थ और आकर्षक वर्णन किया गया है। बच्चे घर में उछलकूद कर सारा घर अस्त-व्यस्त कर देते हैं। जब उन्हें कोई रोकता है तो मन में खीज पैदा होती है। कवि ने बच्चों की इसी चंचलता का पक्ष रखते हुए कहा है-

" मन चाहे मैं बाहर घूमूँ।
मस्ती सब के साथ करूँ।
खेलूँ दौड़ू सबके संग मैं,
कुश्ती में दो हाथ करूँ॥
जी भर के मैं तैरूँ जाकर,

पकड़े तो मैं हाथ न आऊँ।
बचपन चाहता केवल मस्ती,
सबको मैं ये बात बताऊँ॥
नानी-नानी कहो मम्मी से,
इस बन्धन को दूर भगाएँ।
हम सब बच्चे घर से निकलें,
खेलें-कूदें मौज मनाएँ॥"

'बाल प्रज्ञान' बाल कविता संग्रह की उक्त कविताओं के उदाहरणों से स्पष्ट है कि कवि श्री डॉ. सत्यवान सौरभ बालमन के कुशल पारखी हैं। वे बच्चों को भाने वाले विषयों के साथ ही उनके लिए उपयोगी विषयों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। उनका बालमन, बच्चों के साथ बहुत रमता है। संग्रह की शेष रचनाएँ भी बालमन को आकर्षित करने वाली हैं। ये कविताएँ जीवन के विविध पक्षों पर सकारात्मक दृष्टि से विचार करती हुई, बच्चों को संस्कारित करने का काम करती हैं। 'मन को भाता है कम्प्यूटर' कविता में कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर का महत्त्व बताते हुए उसे अनमोल कहा गया है। 'तितली रानी' कविता, आधुनिक समय में पक्षियों के महत्त्व पर प्रकाश डालती है। 'हरियाली तुम आने दो।' रचना, बचपन में बच्चों द्वारा पेड़-पौधें पसंद करने के आनन्द पर आधारित है। 'दादा-दादी' एक बाल सजल है जिसमें बच्चों की दादी के घर जाने की उत्सुकता अभिव्यक्त की गई है। दादी के घर में बच्चों को दादा-दादी, बुआ और चाचा का प्यार मिलता है।

'करो स्कूल की सब तैयारी' कविता बच्चों के विद्यालय जाने के उत्साह को शब्दायित करती है। 'कितने सारे आम' कविता में पेड़ पर लटके कच्चे-पक्के आम बच्चों को लुभाते हैं। 'सेहत का खजाना' कविता में सब्जियों के गुणों का बखान किया गया है। 'पुलिस हमारे देश की' कविता, बच्चों में देश सेवा की भावना को लाती है। 'सदा तिरंगा यूं लहराये' कविता, बच्चों को अच्छी बातें अपनाकर जीवन को सफल बनाने का संदेश देती है। 'चिट्ठी' कविता में आज के समय में चिट्ठियों के नहीं लिखने पर चिन्ता व्यक्त की गई है। चिट्ठियाँ नहीं आने से डाकिया भी बहुत दिनों के बाद कभी-कभार ही दिखाई देता है।

'गिलहरी' कविता में छुट्टी के दिन बच्चों द्वारा पार्क में पिकनिक मनायेजाते वक़्त गिलहरी का सजीव वर्णन है। 'प्यारी चिड़िया रानी' कविता में मानव द्वारा जंगलों को उजाड़ने के कारण वन्य जीवों पर आए संकट का मार्मिक चित्रण है। 'दूधवाला' कविता में कवि मार्मिकचित्र बनाता है, 'फूलों की सीख' कविता में रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई है। 'चंदा मामा' कविता बचपन में हिलमिल कर रहे तारों के बीच चाँद सेबच्चों को मिलने वाली सीख को दर्शाती है। 'ऋतु बसन्त है आई' कविता में बसन्त ऋतु में प्रकृति में आए निखार को दर्शाया गया है। 'आ री आ, ओरी गौरैया' कविता में छोटी—सी चिड़िया गौरैया के प्रति बच्चों के प्रेम को चित्रित किया गया है। 'पूसी-मौसी, मरियल-मंकी' कविता में पूसी बिल्ली, मरियल मंकी और लालू कुत्ते की दोस्ती के माध्यम से सबको आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश दिया गया है। 'रंग-बिरंगी' कविता में एक बच्चा दादू से पिचकारी खरीदने को कहता है ताकि वह अपने मित्रो के साथ मस्ती से होली खेल सके। यह कविता, त्यौहारों के प्रति बच्चों के उत्साह को प्रकट करती है।

बाल कविता संग्रह 'बाल प्रज्ञान' की सभी कविताएँ कवि के मौलिक और यथार्थपरक चिन्तन पर आधारित हैं जो बच्चों को अपने आस-पास के परिवेश की महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती हैं। ये कविताएँ जहाँ आज के बच्चों की शहरी जीवन शैली का परिचय कराती हैं, वहीं कवि के प्रकृति के प्रेम का भी परिचय देती हैं। ये कविताएँ आधुनिक भावबोध की कविताएँ हैं जो बदली परिस्थितियों का सामना करने के लिए बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करती हैं। इन कविताओं की भाषा पढ़े-लिखे परिवारों की बोलचाल की भाषा है जिसमें हिन्दी और अंग्रेज़ी के शब्दों का मिलाजुला प्रयोग होता है। ये कविताएँ बच्चों से सम्बन्धित विषयों को संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच के साथ उजागर करती हैं। कवि ने समसामयिक विषयों को बालमन की कोमलता के साथ स्पर्श किया है। बच्चों से संवाद करती ये कविताएँ बालमन को मनोरंजन प्रदान करने के साथ ही उन्हें स्वस्थ चिन्तन के लिए प्रेरित करती हैं। बालोपयोगी सुन्दर कृति 'बाल प्रज्ञान' के सर्जन के लिए कविवर श्री डॉ। सत्यवान सौरभ जी को हार्दिक बधाई।

-सुरेश चन्द्र 'सर्वहारा'
3फ 22 विज्ञान नगर, कोटा

महाराष्ट्र में महायुति को ज़बरदस्त चुनावी रणनीति ने अभूतपूर्व जीत का इतिहास रचाया !

कार्यकर्ताओं से पर्चियां में फीडबैक लाडली बहन योज़ना व दो नारों ने जबर्दस्त जीत का तोहफ़ा दिया भारत की ख़ूबसूरत लोकतांत्रिक प्रणाली व बुद्धिजीवी सटीक मतदाताओं की निर्णय क्षमता पर दुनियाँ हैरान- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर सारी दुनियाँविश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के चुनावी महापर्व को हैरत भरी नजरों से देखती है कि, उनके पूरे देश के नागरिकों या जनसंख्या वाला तो भारत में एक ही राज्य है, ऐसे 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो कितना बड़ा चुनावी महापर्व होता होगा, आज हम इस विषय पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कल दिनांक 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र व झारखंड राज्यों व अनेक राज्यों के उपचुनाव परिणामों का ऐलान हुआ, जिसके लिए मैंने तीन सटीक विश्लेषण दिए थे, तीनों विश्लेषण हंड्रेड परसेंट सटीक साबित हुए अब हम इसे आगे बढ़ाकर राज्यों में सरकारी बनाने का विश्लेषण व जीत के कारणों पर चर्चा करेंगे,चूँकि झारखंड में तो सीएम झामुमो का ही होगा परंतु सबकी नज़रें महाराष्ट्र पर लगी हुई है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सीएम एकनाथ शिंदे ही रहेंगे, हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यानी 288 में से 132 सीटें शिवसेना 57 व एनसीपी को 41 सीटें मिली है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, सबकी नज़र है, बीजेपी का सीएम होगा। 23 नवंबर 2024 को उद्धव ठाकरे साहब ने भी सीएम बीजेपी का होने होना चाहिए ऐसी बातें कहीं। मेरा व्यक्तिगत निजी मानना है कि सीएम एकनाथ शिंदे साहब भी हो सकते हैं क्योंकि बीजेपी की यह सटीक रणनीति का हिस्सा हो सकता है,जिसका आगे अन्य राज्यों में चुनावों में बीजेपी को बहुत फायदा व महाराष्ट्र में अनेक मुद्दों पर भी फायदा होगा, जिसकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे। चूँकि भारत की खूबसूरत लोकतंत्र प्रणाली व बुद्धिजीवी सटीक मतदाताओं पर दुनियाँ हैरान है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र में महायुति को जबरदस्त चुनावी रणनीति ने, अभूतपूर्व जीत का इतिहास रचाया।

साथियों बात अगर हम 23 जुलाई 2024 को आए महाराष्ट्र के चुनावी परिणामों की करें तो,बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन महायुति ने शानदार जीत दर्ज की है, राज्य में एक बार फिर उसकी सरकार बन रही है।288 सीटों वाले महाराष्ट्रविधानसभा में महायुति को 230 से ज्यादा सीट मिल रही हैं, वहीं एमवीए को 47 सीटें मिली हैं।राज्य में बंपर बहुमत के बाद महायुति में अब सीएम पद को लेकर माथापच्ची होगी। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि तीनों पार्टियां मिलकर फैसला लेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये तय नहीं है कि जिसकी ज्यादा सीटें आई हैं सीएम उसका ही बनेगा।महाराष्ट्र में बंपर जीत पर आयोजित आभार कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन के लिए ये सबसे बड़ी जीत है, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा की लीडरशिप में किसी गठबंधन को महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिया है, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र की गुत्थी महायुति ने सुलझा ली और बंपर जीत के साथ वापसी की है। महायुति का हिस्सा बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी तीनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और महायुति का स्ट्राइक रेट करीब 73 पर्सेंट तक पहुंचा दिया। महायुति का मुकाबला महा विकास अघाड़ी से था।इस गठबंधन की मुख्य पार्टियां कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी हैं। महाविकास अघाड़ी की कोई भी पार्टी सही प्रदर्शन नहीं कर पाई और महा विकास अघाड़ी का स्ट्राइक रेट करीब 17 पर्सेंट के आसपास रहा।महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर यानी 149 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88 पर्सेंट के आसपास है।एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर लड़ी थी और इनका स्ट्राइक रेट भी करीब 69 पर्सेंट रहा। अजीत पवार की एनसीपी 66 सीटों पर लड़ी थी और स्ट्राइक रेट करीब 63 पर्सेंट रहा। महायुति की जो सबसे बड़ी टेंशन थी वह इसे लेकर थी कि अजीत पवार की पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी और क्या वह अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर पाएगी। नतीजों से लगता है कि वोट ट्रांसफर हुआ है। अजीत पवार की इस चुनाव में मजबूत बनकर उभरे हैं। एकनाथ शिंदे की इमेज का भी महायुति को भी बहुत फायदा पहुंचा।

साथियों बात अगर हम महाराष्ट्र के 5 माह पूर्व लोकसभा चुनाव में आए खराब प्रदर्शन को बड़ी ऐतिहासिक जीत में पलटाने की रणनीति की करें तो, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान 48 में सिर्फ 18 सीटें पाने वाली भाजपा नीत महायुति गठबंधन ने छह महीने में ही बाजी पलट दी। अचूक रणनीति और सफल चुनाव प्रबंधन से अबकी बार 200 पार का नारा सफल हुआ और महायुति की महाविजय हुई। महायुति ने छह माह में बाजी पलटने पर संगठन और सरकार के स्तर पर एकसाथ और कारगर प्रयास किए जिसका नतीजा रेकॉर्डतोड़ जीत के रूप में सामने आया। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित विपक्ष का माहौल बदलने के लिए उसका नैरेटिव तोडना बड़ी चुनौती थी लेकिन महायुति इसमें सफल रही भाजपा नेतृत्व ने 10 हजार आम कार्यकर्ताओं से पर्चियों के जरिए 5 से 6 सुझाव मांगे थे। हर जिले के कार्यकर्ताओं से पार्टी ने फीडबैक लेकर समय रहते कमियां दूर कीं। खास बात है कि भाजपा ने हर विधानसभा में गठबंधन के तीनों दलों के नेताओं की कॉर्डिनेशन कमेटियां बनाईं। जिससे तालमेल का संकट खड़ा नहीं हुआ।महिला मतदाताओं को साधने के लिए चलाई गई लाडक़ी बहिन योजना सफल रही। चुनाव से पहले तक ढाई करोड़ महिलाओं के खाते में तीन बार 1500-1500 रुपये भेजकर महायुति सरकार ने विश्वसनीयत हासिल की।उसे इसका लाभ मिला। टोल टैक्स हटाने, वृद्धावस्था पेंशन बढाने और प्याज एक्सपोर्ट से जुर्डी.शर्तें हटाने, ऋण माफी आदि एलानों से महायुति सरकार किसानों और मध्यवर्गीय मतदाताओं को भी साधने में सफल रही। यही वजह रहा कि पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया।लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाराष्ट्र में विपक्ष के संविधान खतरे में नैरेटिव के कारण दलित और बौद्ध मतदाताओं का बड़ा वर्ग कांग्रेस नेतृत्व महाविकास अघाड़ी की तरफ शिफ्ट हुआ था। ऐसे में भाजपा ने नतीजों के तुरंत बाद दलित और ओबीसी वर्ग की 350 प्रमुख जातियों के नेताओं से मीङ्क्षटग शुरू की। दलित बहुल इलाकों में भाजपा ने संविधान यात्राएं निकालीं । गृहमंत्री के निर्देशन में चुनाव प्रभारी ने 3 महीने तक लगातार अलग-अलक जातियों के नेताओं के साथ बैठकें कर उन्हें पार्टी के साथ लाने में सफल रहे और जिसके जरिए वंचित समाज में संविधान और आरक्षण को लेकर फैले ब्रह्म को पाटने में सराहनीय सफल रहे।

साथियों बात अगर हम महाविकास अघाड़ी की असफलता के कारणों की करें तो,लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने जो प्रदर्शन किया था, उसका फायदा यह गठबंधन नहीं ले पाया। यह न तो सत्ताधारी गठबंधन को मद्दों पर घेर पाया न ही उनके नेरेटिव के जवाब में कोई काउंटर नेरेटिव सेट कर पाया। शिवसेना में बगावत के बाद जब राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार गिरी थी और शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी टूटी को उद्ध ठाकरे और शरद पवार को लेकर सहानुभूति थी जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में दिखा। लेकिन यह गठबंधन विधानसभा चुनाव में इसे भुनाने में असफल रहा। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे इन्होंने उठाए लेकिन उसे लेकर माहौल नहीं बना पाए।लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी द्वारा आक्रामकता से जातिगत जनगणना और संविधान पर खतरे को मुद्दा बनाने के मुद्दे से माहौल बनाया गया था। भाजपा इस नैरेटिव को तोडने में लगी थी लेकिन अति आत्मविश्वास में डूबे एमवीए नेता इसका जवाब नहीं तलाश पाए। उन्होंने भाजपा बंटेंगे तो कटेंगे' और 'एक हैं तो सेफ हैं' जैसे नारों का माकूल जवाब भी समय पर नहीं दिया गया। ऐसे में यह नारे लोगों को लुभा गए। कांग्रेस की गारंटियों जैसे पुराने वादे भी मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पाए साथ ही तालमेल में कमी और शिवसेना से वैचारिक भिन्नता भी कहीं न कहीं नुकसानदेह साबित हुई। कुर्सी की खींचतानदर असल, लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने एकजुटता से चुनाव लड़ते हुए महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जीती। इस दौरान करीब 150 से अधिक विधानसभा सीटों पर इंडिया ब्लॉक की बढ़त रही।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि महाराष्ट्र में महायुति को ज़बरदस्त चुनावी रणनीति ने अभूतपूर्व जीत का इतिहास रचाया !कार्यकर्ताओं से पर्चियां में फीडबैक,लाडली बहन योज़ना व दो नारों ने जबर्दस्त जीत का तोहफ़ा दिया।भारत की ख़ूबसूरत लोकतांत्रिक प्रणाली वबुद्धिजीवी सटीक मतदाताओं की निर्णय क्षमता पर दुनियाँ हैरान है।

भुवनेश्वर में कोई बांग्लादेशी लड़की , सेक्स रैकेट से लेकर दुष्कर्म भी हो रहा है

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : ओडिशा में 23 बांग्लादेशी महिलाएं। उपनगरों में नहीं, बल्कि भुवनेश्वर में युवतियों पर अकथनीय अत्याचार होता है। सेक्स रैकेट से लेकर झुंड सेवाओं तक इन युवतियों का शोषण किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि बांग्लादेश की एक युवती ने कहा है।कुछ दलाल अच्छी नौकरी पाने की चाहत में भारत की सीमा पार कर भुवनेश्वर आये हैं। और उसके बाद इंसान के अंदर के राक्षस ने अपना रूप दिखाने में देरी नहीं की। प्रतिदिन दो हजार रुपये देने की बात कहकर दलाल लाखों रुपये कमा रहा है। एक या दो नहीं, बल्कि 23 युवतियों को कथित तौर पर भुवनेश्वर के एक अपार्टमेंट में रखा गया और उनसे वेश्यावृत्ति कराई गई। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि इन युवा बांग्लादेशी महिलाओं को भुवनेश्वर में किसकी सेवा में नियुक्त किया जा रहा है ? जिसके लिए उन्हें भुवनेश्वर जैसी हाई प्रोफाइल जगह पर लाखों रुपये मकान का किराया देकर एक अपार्टमेंट में सालों से रखा गया है। दुर्भाग्य से फर्जी आधार कार्डों पर उनका घर बांग्लादेश बताया जा रहा है। वे बांग्लादेश नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास वैध पहचान पत्र नहीं है। अपने देश कैसे लौटें ? ये युवतियां इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यहां से कैसे निकला जाए।

कानपुर में ट्रेन के पास आने पर पटरी पार करने की कोशिश में छात्र की मौत, घर में कोहराम

सुनील बाजपेई

कानपुर। तेज रफ्तार ट्रेन के पास आने पर पटरी पार करने की कोशिश एक छात्र की असमय मौत का कारण बन गई। घटना के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस में लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

यह घटना महाराजपुर के भेवली गांव के पास रेलवे ट्रैक पर हुई। यहां रेल पटरी पार करते समय 14 वर्षीय आयुष की वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। वह सातवीं का छात्र था। इस हादसे के बाद करीब पांच मिनट तक ट्रेन वहीं खड़ी रही। इसके बाद आगे के लिए रवाना हुई।

बताते हैं कि आयुष ट्रेन के पास आने पर की पटरी पार करना चाहता था। यही कोशिश उसकी असमय मौत का कारण बन गई।

पुलिस से प्राप्त विवरण के मुताबिक भेवली निवासी मजदूर लालमणि रैदास के मुताबिक, बेटा आयुष दोपहर में सरसौल स्थित स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौटा,लेकिन वहां ताला लगा मिला।

परिवार वालों ने बताया कि इसके बाद आयुष खेत पर मिर्च तोड़ने गई मां रेश्मा के पास पहुंचा और उनसे चाबी लेकर घर जाने लगा। भेवली व हाथीगांव के बीच रेलवे ट्रैक पार करते समय करीब तीन बजे फतेहपुर की तरफ से आ रही वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद उसके परिवार में कोहरा मचा हुआ है वहीं पुलिस ने रात को कब्जे के लिए लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023